Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

हिन्दी दैनिक

E-Mail : mantragwalior@gmail.com

मंत्र भारत

संस्करण : ग्वालियर
वर्ष : 03
अंक : 144
पृष्ठ : 6
मूल्य : 2.00

बुधवार,24 दिसम्बर 2025

ग्वालियर, मुम्बई, लखनऊ एवं प्रयागराज,से एक साथ प्रकाशित एवं गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़ से प्रसारित

3 भाजपा चौधरी चरण सिंह के आदर्शों को पूरा करने | 4 2026 के लिए क्या कहती हैं भविष्यवाणियां | 5 प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी जोनस को क्या है पसंद?

किसान दिवसः सीएम योगी ने किसानों को किया सम्मानित

धरतीपुत्रों के हितों की रक्षा करना सभी का धर्म

■ नए-नए अनुसंधान करके कृषि क्षेत्र को नया आयाम देने का प्रयास- कृषि मंत्री ■ किसान के हितों की रक्षा करना सभी का धर्म है

लखनऊ। किसान दिवस पर सीएम योगी ने किसानों को सम्मानित किया। उन्हें ट्रैक्टर की चाबी सौंपी। कहा कि किसान के हितों की रक्षा करना सभी का धर्म है। सरकार किसानों की उन्नति के लिए लगातार कार्य कर रही है।

राजधानी लखनऊ में मंगलवार को किसान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। साथ ही कई किसानों को ट्रैक्टर की चाबी सौंपी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि प्रदेश के किसानों के हितों की रक्षा करना सभी का धर्म है। किसानों की उन्नति के लिए प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है। यह पहली बार हुआ है कि किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा हैं।2014 में भाजपा सरकार बनने के बाद से लेकर अब तक लगातार किसानों के विकास के लिए प्रयास किया जा रहा है। जब मां बीमार होती है तो पुत्र का दायित्व होता है कि वह उसकी देखरेख करें। पहली बार ऐसा हुआ कि धरती माता के सेहत को लेकर गंभीरता दिखाई गई। सीएम ने आगे कहा कि अब देश का हर किसान सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए अपनी धरती की सेहत का ध्यान रख रहा है। इसके लिए लगातार सरकार की ओर से किसानों को जागरूक किया गया और तरह-तरह के अभियान चलाए गए। उन्होंने किसानों से भारत माता के जयकारे के साथ देश और प्रदेश के विकास में योगदान देने के लिए अपील की। नए-नए अनुसंधान करके कृषि क्षेत्र को नया आयाम देने का प्रयास- कृषि मंत्री कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि हम जय जवान जय किसान और जय विज्ञान के सहारे तरक्की की नई इबारत लिख रहे हैं।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब इस नारे में जय अनुसंधान भी जोड़ दिया है।इससे विकास की गति और तेज हो गई है। भविष्य की रणनीति के तहत नए-नए अनुसंधान करके कृषि क्षेत्र को नया आयाम देने का प्रयास किया जा रहा है। ताकि, वर्ष 2047 के विकसित भारत का सपना साकार हो सके। ये लोग रहे मौजूद कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख, पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह और उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सहित कई मंत्री व आरएलडी के सभी विधायक शामिल रहे।

पीएम मोदी से मिले जैवलिन स्टार नीरज चोपड़ा और पत्नी हिमानी

खेल सहित कई मुद्दों पर हुई बात

नई दिल्ली। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर ने मंगलवार को यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने उनके आवास पर हुई इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में फोटो साझा करते हुए यह जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा , आज सुबह 7 लोक कल्याण मार्ग पर नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर से मुलाकात हुई। हमने खेलों के साथ-साथ विभिन्न विषयों पर बातचीत की। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष के शुरू में मोदी ने फिटनेस को बढावा देने के नीरज चोपड़ा के प्रयासों की सोशल मीडिया पर काफी सराहना की थी। फिट इंडिया योजना के महत्व पर नीरज चोपड़ा के लेख पर प्रतिक्रिया करते हुए श्री मोदी ने कहा था कि यह दूरदर्शी और प्रेरक लेख मोटापे से लड़ने और स्वस्थ रहने की जरूरत पर बल देता है।

सार संक्षेप

नोएडा एयरपोर्ट की साइबर सिक्योरिटी संभालेगी टेक महिंद्रा

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपने नेटवर्क को मजबूत करने और साइबर सुरक्षा ऑपरेशन के लिए महिंद्रा समूह की कंपनी टेक महिंद्रा के साथ करार किया है। दोनों कंपनियों की संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस उद्देश्य के लिए टेक महिंद्रा एकीकृत नेटवर्क एंड सिक्योरिटी ऑपरेशन्स सेंटर स्थापित करेगी। यह हवाई अड्डे पर निर्बाध और सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित करेगा। टेक महिंद्रा नेटवर्क और हवाई अड्डे के आईटी ढांचे के लिए 24 गुना 7 निगरानी एवं प्रबंधन मुहैया करायेगी। इसमें एप्लिकेशन्स, डाटाबेस, नेटवर्क, सर्वर, स्टोरेज सिस्टम और संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल होंगे। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टफ स्नेलमैन ने कहा, एक नये हवाई अड्डे के तौर पर हमारे पास नेटवर्क की मजबूती, सुरक्षा और डिजिटल इकोसिस्टम में पहले दिन से ही परिचालन की उत्कृष्टता शामिल करने का अवसर है। टेक महिंद्रा के साथ हमारी सहभागिता एक मजबूत और भविष्य के लिए तैयार नेटवर्क तथा साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क तैयार करने की दिशा में एक कदम है। इससे सुरक्षित, भरोसेमंद और निर्बाध परिचालन सुनिश्चित हो सकेगा।

बांग्लादेश में हिंदू युवक की लिंचिंग के खिलाफ राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन

नईदिल्ली। पिछले हफ्ते बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू युवक की भीड़ ने हत्या कर दी. इस घटना के विरोध में, 23 दिसंबर को नयी दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन हुआ, जिसमें शामिल लोगों की संख्या सैकड़ों में बताई जा रही है. समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, यह प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हुआ.प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की तस्वीरें जलाईं और उनके खिलाफ नारे लगाए. बांग्लादेश के बहिष्कार की मांग करते पोस्टर दिखे. टीवी फुटेज में दिखा कि प्रदर्शनकारियों ने हाई कमीशन के बाहर लगे बैरिकेडों को पार करने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प हुई.एक प्रदर्शनकारी ने इंडिया टुडे से कहा, हमें जरूरत थी कि दिल्ली में बांग्लादेश के हिंदुओं की आवाज उठाएं और हमने यह कर दिया. जब तक वहां एक भी हिंदू को नुकसान पहुंचाया जाएगा, हम नहीं रुकेंगे. इससे पहले 20 दिसंबर को भी एक प्रदर्शन हुआ था. बांग्लादेश ने कहा है कि प्रदर्शनों के मद्देनजर भारतीय राजदूत को तलब किया गया और घटनाओं की तफ्तीश करने की मांग की गई।

यूपी विधानसभा ने किसान नेता चरण सिंह को उनकी जयंती पर किया याद, अर्पित की श्रद्धांजलि

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन संपूर्ण सदन ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर याद किया और उनके कार्यों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों के हित में उल्लेखनीय कार्य किया।कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विधानसभा में शून्यकाल में चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें स्मरण करते हुए कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज जयंती है। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री, कृषि व राजस्व मंत्री के रूप में किसानों के हित में उल्लेखनीय कार्य किया। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह की सरकार में उनके जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया

गया था।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के सपूत चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न वर्ष 2024 में दिया। उन्होंने कहा, योगी सरकार ने उनकी स्मृतियों को चिरकाल तक स्मरणीय बनाये रखने के लिए 23 दिसंबर 2025 को भारत रत्न चौधरी चरण सिंह सीड पार्क को शुरू किया है, जिससे राज्य के अन्नदाता किसान को उत्कृष्ट बीज सुलभ हो सके और किसान बीज दाता किसान बनकर चौधरी साहब के सपनों को साकार कर सकें। शाही ने कहा, वर्तमान में सत्र चल रहा है इसलिए चरण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अपना वक्तव्य दे रहा हूं।उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने पटवारी और जमींदारी प्रथा समाप्त करके किसानों को अपने खेत का मालिक बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि व्यापारी और बिचौलियों द्वारा किसानों का शोषण बंद करने के लिए मंडी की स्थापना के लिए उनको सदैव याद किया जाएगा। शाही ने कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के रूप में सरल और सादगी के प्रतीक चरण सिंह ने हर वर्ग के हित में काम किया। सामाजिक सुधारों के लिए देश सदैव उनका कृतज्ञ रहेगा। उन्होंने चरण सिंह को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए कहा, आज चौधरी साहब का जन्मदिन है और मुझे उनके निकट रहने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में किसानों की बात करने सबसे पहले चौधरी चरण सिंह आगे आये और काफी संघर्ष किया। पांडेय ने कहा कि जब वे उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री थे तो उन्होंने जमींदारी उन्मूलन किया और छोटे किसानों को उनकी भूमि पर स्ध्वामित्ध्व दिया। उन्होंने कहा कि जब पूरे देश में नक्सली आंदोलन चल रहा था, तब उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की नीतियों के कारण शांति व्यवस्था थी।

कुलदीप सेंगर को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने निलंबित की आजीवन कारावास की सजा

शर्तों पर मिली जमानत

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे भाजपा के निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की सजा मंगलवार को निलंबित कर दी। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर ने 15 लाख रुपये के निजी

मुचलके और इतने की ही तीन जमानत राशियां जमा करने का निर्देश देकर सेंगर को जमानत दे दी। उच्च न्यायालय ने सेंगर को निर्देश दिया कि वह न तो पीड़िता के घर के पांच किलोमीटर के दायरे में जाएंगे और न ही उसे या उसकी मां को कोई धमकी देंगे। अदालत ने कहा, शर्तों का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। उच्च न्यायालय ने बलात्कार मामले में दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील लंबित रहने तक सेंगर की सजा पर रोक लगाई है। उसने दिसंबर 2019 के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। संबंधित मामले के अनुसार, सेंगर ने 2017 में नाबालिग लड़की का अपहरण कर बलात्कार किया था। उच्चतम न्यायालय के एक अगस्त 2019 के निर्देश के आधार पर बलात्कार और अन्य संबंधित मामले उत्तर प्रदेश की एक निचली अदालत से दिल्ली स्थानांतरित कर दिए गए थे। पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत होने से संबंधित मामले में सजा के खिलाफ सेंगर की अपील अब भी लंबित है।इस अपील में उसने यह कहते हुए सजा निलंबित करने का आग्रह किया है कि वह पहले ही जेल में काफी समय बिता चुका है। हिरासत में मौत के मामले में उसे 10 साल की सजा सुनाई गई थी।

यूपी गैंगस्टर विकास दुबे पर बनी वेब सीरीज को नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपी 77 की रिलीज रोकने की याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कथित तौर पर गैंगस्टर विकास दुबे के जीवन पर आधारित वेब सीरीज यूपी 77 को रिलीज किए जाने से रोकने की याचिका पर केंद्र सरकार और वेब सीरीज निमार्ताओं से जवाब मांगा। यह याचिका मुठभेड़ में मारे गए दुबे की पत्नी ने दायर की है। वेब सीरीज 25 दिसंबर को ओटीटी मंच वेव्स पर रिलीज होने वाली है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई बुधवार के लिए निर्धारित की। दुबे 2020 में उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में मारा गया था। राज्य पुलिस के अनुसार, कानपुर में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपी दुबे ने मध्यप्रदेश के उज्जैन में आत्मसमर्पण कर दिया था और उसे उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था, तभी उसे ले जा रहा वाहन पलट गया और दुबे ने कथित तौर पर भागने का प्रयास किया।

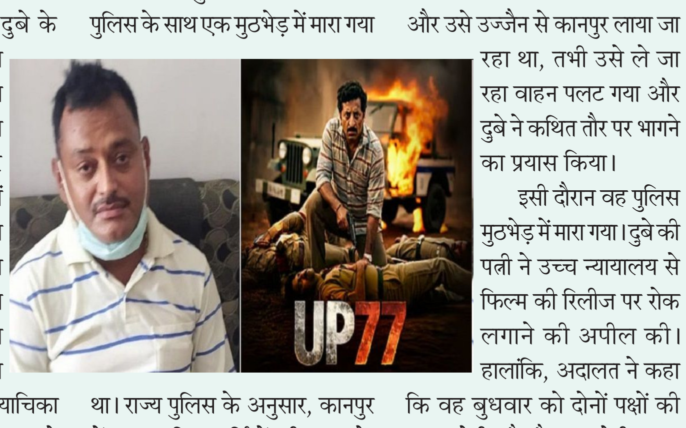

इसी दौरान वह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। दुबे की पत्नी ने उच्च न्यायालय से फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की अपील की। हालांकि, अदालत ने कहा कि वह बुधवार को दोनों पक्षों की बात सुनेगी और फैसला लेगी।

क्रिसमस और नए साल से पहले बढ़ाई गई दिल्ली की सुरक्षा

सीमावर्ती इलाके में तैनात किये गए जवान

नईदिल्ली। क्रिसमस और नए साल के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने मजबूत सुरक्षा प्रबंध किए हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 20,000 पुलिस और अर्धसैनिक कर्मियों को तैनात किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। राष्ट्रीय राजधानी के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। दिल्ली की सीमाएं उत्तर प्रदेश व हरियाणा से लगती है जो राजस्थान से निकट है। नव वर्ष मनाने के लिए इन राज्यों से बड़ी संख्या में लोगों के शहर में आने की उम्मीद है। अधिकारी ने कहा कि यातायात और अर्धसैनिक बलों सहित लगभग 20,000 पुलिसकर्मी गुंडागर्दी और

यातायात नियमों के उल्लंघन के रोकथाम के लिए मौके पर तैनात रहेंगे। अधिकारी ने बताया कि पड़ोसी राज्यों के लोगों के संभावित उपद्रव से निपटने के लिए सीमाओं पर अतिरिक्त नाके बनाए जाएंगे और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्रिसमस के मद्देनजर 10 से अधिक स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया जा चुके हैं और सुरक्षा जांच को और भी कड़ा किया जाएगा। दिल्ली में 15 और उन स्थानों पर भी पुलिस तैनात की जाएगी जहां गाड़ियां राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करती है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, यातायात पुलिस ने मोटरसाइकिल से किए जाने वाले स्टंट और शराब पीकर गाड़ी चलाने से निपटने के लिए पहले ही योजना बना ली है। यातायात पुलिस की सहायता के लिए विभिन्न थानों से अतिरिक्त बल तैनात किए जाएंगे। अधिकारी ने बताया कि पुलिस कर्मियों को पाली के अनुसार तैनात किया जाएगा। थानेदारों (एसएचओ) को क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी टीमों के साथ सड़कों पर मौजूद रहने का आदेश दिया गया है। यदि कोई भी स्टंट जैसी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो टीमें तुरंत दो या चार पहिया वाहनों को जब्त कर लेंगी।

आप किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? इसकी जांच होनी चाहिए :पवन खेड़ा

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के 2013 के नक्सली हमले को लेकर किए गए दावे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे दावों को बिना चुनौती दिए नहीं छोड़ा जा सकता।इसी बीच, पवन खेड़ा ने जेपी नड्डा के दावों को लेकर जांच की मांग की।केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पिछले दिन दावा किया कि 2013 के नक्सली हमले में कांग्रेस के लोग शामिल थे। इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पूछा, उस समय रमन सिंह की सरकार थी। क्या इसका मतलब है कि उनकी सरकार फेल हो गई? समाचार एजेंसी से बातचीत में पवन खेड़ा ने कहा, बारह साल के बाद आप अब क्यों बोल रहे हैं? आप किसे बचाने या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? इसकी जांच होनी चाहिए। जेपी नड्डा को क्या पता है, और वह इतने सालों से चुप क्यों थे? उनसे पूछताछ होनी चाहिए।उन्होंने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की ओर से बिहार सरकार की तारीफ को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, जब वह (शशि थरूर) दिल्ली लौटेंगे, तो मैं जरूर कुछ दिनों के लिए उनका चश्मा उधार लूंगा, ताकि बिहार को वैसे ही देख सकूं जैसे वह देखते हैं।राहुल गांधी के इस बयान पर कि ‘भारत ने प्रोडक्शन चीन को सौंप दिया।

जेपी नड्डा की अध्यक्षता में भाजपा सांसदों की पहली बैठक

नईदिल्ली। बैठक के दौरान भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का पार्टी के सांसदों से औपचारिक परिचय कराया जाएगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ बैठक में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसदों की पहली बैठक मंगलवार को होगी, जिसकी अध्यक्षता भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन करेंगे। यह बैठक मंगलवार को रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। भाजपा सूत्रों के अनुसार, बैठक में संसद खेल महोत्सव के सफल आयोजन की रणनीति को अंतिम रूप देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पार्टी सूत्रों ने बताया, ‘बैठक का मुख्य उद्देश्य संसद खेल महोत्सव के सफल आयोजन को सुनिश्चित करने की रणनीति को अंतिम रूप देना है। आयोजन से संबंधित समन्वय और तैयारियों पर विस्तृत चर्चा होगी। बैठक के दौरान भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का पार्टी के सांसदों से औपचारिक परिचय कराया जाएगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ बैठक में शामिल होंगे। सभी भाजपा सांसदों के बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री 25 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। आज की बैठक में समापन समारोह से पहले की तैयारियों और व्यवस्थाओं की समीक्षा और चर्चा भी की जाएगी। नबीन आज बिहार में विभिन्न पार्टी कार्यक्रमों में भाग लेने और कार्यकताओं तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के बाद यह उनकी पहली बिहार यात्रा है। 45 वर्ष की आयु में नबीन पार्टी में अब तक चुने गए सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष हैं। वे बिहार मंत्रिमंडल में सड़क निर्माण मंत्री भी हैं। भाजपा ने 14 दिसंबर को नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया, जो पार्टी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण पीढ़ीगत बदलाव का प्रतीक है। भाजपा सूत्रों के अनुसार, उनका चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ा हुआ है। भाजपा नेतृत्व का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि 2047 तक, जब भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाए, पार्टी के पास एक परिपक्व और अनुभवी नेतृत्व हो।

राष्ट्रीय सम्मेलन में नदियों और जल निकायों को बहाल करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी का आह्वान किया गया

नई दिल्ली,: नेचर केयर इनिशिएटिव (एनसीआई) द्वारा 'नदियों और जल निकायों के स्वास्थ्य को बहाल करना' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन शनिवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण में सार्वजनिक भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सभा को संबोधित करते हुए, राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार ने कहा कि नदियों और जल निकायों का पुनरुद्धार केवल सरकारी कार्रवाई के माध्यम से हासिल नहीं किया जा सकता है। ह्रसामुदायिक स्वामित्व आवश्यक है,ह्व उन्होंने कहा, पर्यावरण की दृष्टि से

जिम्मेदार जीवनशैली के माध्यम से सार्थक परिवर्तन घरेलू स्तर पर शुरू होना चाहिए। उन्होंने कहा, ह्रनागरिकों का हर छोटा प्रयास बड़े परिवर्तन में योगदान देता है। इन विचारों को दोहराते हुए, दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रमुख प्रोफेसर दीनबंधु साहू ने जोर देकर कहा कि पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान के लिए सार्वजनिक भागीदारी अपरिहार्य है। गंगा-यमुना एक्शन प्लान में पर्याप्त निवेश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि खर्च के बावजूद नदियों को बहाल करने का काम अधूरा है। उन्होंने नागरिकों से इस मुद्दे को अपना मुद्दा मानने और समाधान खोजने में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। प्रोफेसर साहू ने दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण संकट के समाधान के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों की भी वकालत की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वकील सौम्यजीत पाणि ने छोटे शहरों से लेकर महानगरीय शहरों तक शहरी परिदृश्य में सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। दक्षिण एशिया जलवायु परिवर्तन पत्रकार मंच के अध्यक्ष आशीष गुप्ता ने प्रौद्योगिकी, नीति अभिसरण और निरंतर सार्वजनिक भागीदारी के मिश्रण के माध्यम से नदी बहाली की आवश्यकता पर जोर दिया। 'नदियों और जल निकायों की सफाई में सामुदायिक भागीदारी' शीर्षक वाले एक तकनीकी सत्र में वाईएसएस फाउंडेशन के निदेशक सचिन गुप्ता; कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (KIIT), भुवनेश्वर में सिविल इंजीनियरिंग विभाग की प्रमुख डॉ. संजुक्ता साहू; और दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में सहायक प्रोफेसर डॉ. धर्मेंद्र कुमार ने नागरिक नेतृत्व वाली पर्यावरणीय कार्रवाई के लिए एक व्यापक रोडमैप की रूपरेखा तैयार की। कार्यक्रम के दौरान, प्रो. दीनबंधु साहू को प्रकृति-आधारित समाधानों के लिए नेचर केयर अवार्ड, 2025 से सम्मानित किया गया। नेचर केयर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड, 2025, सचिन गुप्ता, डॉ. धर्मेंद्र कुमार और डॉ. संजुक्ता साहू को प्रदान किया गया।

तस्वीरों में देखें- दिव्यांग खिलाड़ियों का हौसला गेंदबाजी और गेंदबाजी में किया शानदार प्रदर्शन

वाराणसी। दिव्य शक्ति सुगम्य भारत ट्रॉफी का फाइनल उत्तर प्रदेश और राजस्थान की टीमों के बीच खेला गया। बीएचयू के एंफिथियेटर मैदान पर खेली गई प्रतियोगिता में दीप्रेंद्र सिंह के ताबड़तोड़ 44 रन से यूपी ने ट्रॉफी जीती। डिफरेंटली एबल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया व ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दिव्य शक्ति सुगम भारत ट्रॉफी सोमवार को संपन्न हुई। दिव्य शक्ति सुगम्य भारत ट्रॉफी का

फाइनल उत्तर प्रदेश और राजस्थान की टीमों के बीच बीएचयू के एंफिथियेटर मैदान पर खेला गया। सुरेंद्र की अर्द्धशतकीय पारी के बाद भी राजस्थान की टीम जीत न सकी। यूपी टीम के दीप्रेंद्र सिंह के ताबड़तोड़ 44 रन बनाकर यूपी को ट्रॉफी जिताई। टॉस जीतकर राजस्थान के कप्तान जसवंत सिंह ने गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी कर यूपी की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 161 रन बनाए। दीपेंद्र सिंह ने 25 गेंद में 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से ताबड़तोड़ 44 रन बनाए। गेंदबाजी में राजस्थान के कप्तान जसवंत सिंह ने 4 ओवरों में 23 रन देकर तीन विकेट लिए। 162 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम लगातार अंतराल पर विकेट गवाती रही। टीम के सुरेंद्र कुमार ने 40 गेंद में 53 रनों (3 चौके, 3 छक्के) की अर्द्धशतकीय पारी खेली। इसके बाद भी टीम को जीत नहीं दिला सके। राजस्थान की टीम 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 139 रन ही बना सकी। यूपी ने 22 रनों से जीत लिया। यूपी के कुमार राहुल मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। लीग के बेस्ट बल्लेबाज का खिताब यूपी टीम के दीपेंद्र सिंह और बेस्ट बॉलर कुमार राहुल बने। मैन ऑफ द सीरीज सुरेंद्र कुमार बने। विजेता व उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को समाजसेवी केशव जालान ने पुरस्कृत किया। संचालन डॉ संजय चौरसिया, धन्यवाद डॉ उत्तम ओझा ने किया। इस मौके पर मीडिया प्रभारी भाजपा काशी क्षेत्र नवरतन राठी, महामंडलेश्वर दिव्यांग पीठाधीश्वर कृपानंद, अशोक चौरसिया, रवि चौहान, सुनीता तिवारी, निधि अग्रवाल मौजूद रहे।

यशोदा नगर एलिवेटेड रोड पर कोहरे का कहर पिकअप पलटीा

कानपुर। यशोदा नगर एलिवेटेड पर कोहरे के कारण टमाटर लदी पिकअप पलट गई। चेचिस में फंसे दो युवकों को फायर ब्रिगेड ने दो घंटे के रेस्क्यू के बाद गैस कटर से काटकर सुरक्षित निकाला। कानपुर में घने कोहरे और धुंध के कारण मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यशोदा नगर एलिवेटेड रोड पर टमाटर से लदी एक पिकअप अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में दो युवक गाड़ी की चेचिस के बीच बुरी तरह फंस गए, जिन्हें फायर ब्रिगेड की टीम ने दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार, पिकअप टमाटर लादकर रामादेवी की ओर जा रही थी। घने कोहरे की वजह से दृश्यता कम थी, जिससे गाड़ी सीधे डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और उसमें सवार दो युवक चेचिस के बीच दब गए। सूचना मिलते ही किदवई नगर के फायर अधिकारी कामता प्रसाद अपनी टीम के साथ पहुंचे। हाईवे पर लगा घंटों लंबा जाम फायर कर्मियों ने गैस कटर का इस्तेमाल कर गाड़ी के लोहे के हिस्सों को काटा और करीब दो घंटे बाद दोनों युवकों को मौत के मुंह से सकुशल बाहर निकाल लिया। हादसे और रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते एलिवेटेड रोड पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया। नौबस्ता से रामादेवी जाने वाले मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस ने क्षतिग्रस्त पिकअप को क्रेन की मदद से हटवाकर रास्ता सुचारू कराया।

किशोरियों संग अश्लील हरकत करने पर एफआईआर

बस्ती। हरैया पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर किशोरियों संग अश्लील हरकत के मामले में एफआईआर दर्ज किया है। थानाक्षेत्र के रहने वाले शिकायतकर्ता ने तहरीर में आरोप लगाया है कि उनके गांव के रहने वाले एक युवक समेत दो लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर उन्हें अपशब्द कहा। मना करने पर जान से मारने की धमकी दी। एक सितंबर को छत पर उनकी 11 वर्षीय व 12 वर्षीय दो बेटियां सो रही थीं। छत पर चढ़कर आरोपियों ने दुष्कर्म की नीयत से बेटियों के साथ छेड़खानी की। बच्चियों के विरोध के बाद दोनों भाग निकले।

लड़कियों को देखकर अश्लील गाना गाने पर एफआईआर

बस्ती। मुंडेरवा पुलिस ने लड़कियों को देखकर अश्लील गाना गाने व अश्लील टिप्पणी करने के मामले में एफआईआर दर्ज किया है। थाने के एसआई जावेद खान ने तहरीर देकर बताया है क्षेत्र के एक स्कूल के सामने चाय की दुकान पर आरोपी विक्रम गौड़ प्रतिदिन विद्यालय में लड़कियों के आने-जाने के समय पर मौजूद रहकर अश्लील गाना गाता रहता है और अश्लील बातें कहता है।

2026 तक प्रतिदिन 04 अनारक्षित रिंग रेल सेवा चलाये जाने का निर्णय लिया गया है

गोरखपुर,: रेलवे प्रशासन द्वारा प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला के अवसर पर श्रद्धालु यात्रियों की होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुये 02 जनवरी से 17 फरवरी, 2026 तक प्रतिदिन 04 अनारक्षित रिंग रेल सेवा चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। फलस्वरूप 04111 प्रयागराज जं.-प्रयागराज रामबाग-बनारस-जंघई-जफराबाद-अयोध्या धाम- प्रयाग-प्रयागराज जं. रिंग रेल अनारक्षित विशेष गाड़ी 02 जनवरी से 17 फरवरी, 2026 तक प्रतिदिन प्रयागराज जं. से 06.00 बजे प्रस्थान कर प्रयागराज रामबाग से 06.12 बजे, झूसी से 06.30 बजे, हंडिया खास से 06.52 बजे, ज्ञानपुर रोड से 07.17 बजे, माधोसिंह से 07.35 बजे, बनारस से 08.20 बजे, भदोही से 09.15 बजे, जंघई से 10.00 बजे, मड़ियाहू से 10.35 बजे, जफराबाद से 11.02 बजे, जौनपुर से 11.20 बजे, शाहगंज से 11.57 बजे, अकबरपुर से 12.50 बजे, गोशाईंगंज से 13.17 बजे, अयोध्या धाम से 14.15 बजे, अयोध्या कैंट से 14.32 बजे, सुलतानपुर से 15.35 बजे, माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ से 16.32 बजे, मऊ आइमा से 17.17 बजे, फफामऊ से 18.02 बजे तथा प्रयाग से 18.22 बजे छूटकर प्रयागराज जं. 18.50 बजे पहुँचेगी। 04113 प्रयागराज जं.-प्रयागराज रामबाग-बनारस-जंघई-जफराबाद-अयोध्या धाम- प्रयाग-प्रयागराज जं. रिंग रेल अनारक्षित विशेष गाड़ी 02 जनवरी से 17 फरवरी, 2026 तक प्रतिदिन प्रयागराज जं. से 17.30 बजे प्रस्थान कर प्रयागराज रामबाग से 17.42 बजे, झूसी से 18.00 बजे, हंडिया खास से 18.22 बजे, ज्ञानपुर रोड से 18.47 बजे, माधोसिंह से 19.05 बजे, बनारस से 19.50 बजे, भदोही से 20.55 बजे, जंघई से 21.40 बजे, मड़ियाहू से 22.15 बजे, जफराबाद से 22.42 बजे, जौनपुर से 23.00 बजे, शाहगंज से 23.37 बजे, दूसरे दिन अकबरपुर से 00.30 बजे, गोशाईंगंज से 00.57 बजे, अयोध्या धाम से 02.15 बजे, अयोध्या कैंट से 02.32 बजे, सुलतानपुर से 03.40 बजे, माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़से04.42 बजे, मऊ आइमा से 05.32 बजे, फफामऊ से 06.17 बजे तथा प्रयाग से 07.02 बजे छूटकर प्रयागराज जं. 07.45 बजे पहुँचेगी। 04114 प्रयागराज जं.- प्रयाग-अयोध्या धाम-जफराबाद-जंघई-बनारस-प्रयागराज रामबाग- प्रयागराज जं. रिंग रेल अनारक्षित विशेष गाड़ी 02 जनवरी से 17 फरवरी, 2026 तक प्रतिदिन प्रयागराज जं. से 17.45 बजे प्रस्थान कर प्रयाग से 18.00 बजे, फाफामऊ से 18.12 बजे, मऊ आइमा से 18.57 बजे, माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ से 19.42 बजे, सुलतानपुर से 20.40 बजे, अयोध्या कैंट से 21.47 बजे, अयोध्या धाम से 22.20 बजे, गोशाईंगंज से 23.07 बजे, अकबरपुर से 23.35 बजे, दूसरे दिन शाहगंज से 00.27 बजे, जौनपुर से 01.10 बजे, जफराबाद से 01.25 बजे, मड़ियाहू से 01.52 बजे, जंघई से 02.50 बजे, भदोही से 03.30 बजे, बनारस से 04.25 बजे, माधोसिंह से 05.12 बजे, ज्ञानपुर रोड से 05.57 बजे, हंडिया खास से 06.40 बजे, झूसी से 07.12 बजे तथा प्रयागराज रामबाग से 07.30 बजे छूटकर प्रयागराज जं. 08.00 बजे पहुँचेगी। 04120 प्रयागराज जं.- प्रयाग-अयोध्या धाम-जफराबाद-जंघई-बनारस-प्रयागराज रामबाग- प्रयागराज जं. रिंग रेल अनारक्षित विशेष गाड़ी 02 जनवरी से 17 फरवरी, 2026 तक प्रतिदिन प्रयागराज जं. से 13.30 बजे प्रस्थान कर प्रयाग से 13.45 बजे, फाफामऊ से 13.57 बजे, मऊ आइमा से 14.42 बजे, माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ से 15.30 बजे, सुलतानपुर से 16.25 बजे, अयोध्या कैंट से 17.32 बजे, अयोध्या धाम से 18.05 बजे, गोशाईंगंज से 18.52 बजे, अकबरपुर से 19.20 बजे, शाहगंज से 20.12 बजे, जौनपुर से 20.55 बजे, जफराबाद से 21.10 बजे, मड़ियाहू से 21.37 बजे, जंघई से 22.40 बजे, भदोही से 23.15 बजे, दूसरे दिन बनारस से 00.10 बजे, माधोसिंह से 01.17 बजे, ज्ञानपुर रोड से 01.50 बजे, हंडिया खास से 02.50 बजे, झूसी से 03.17 बजे तथा प्रयागराज रामबाग से 03.32 बजे छूटकर प्रयागराज जं. 04.00 बजे पहुँचेगी। यह गाड़ी मेमू रेक से चलाई जायेगी।

लाखों का पैकेज विदेश का ऑफर छोड़ खेती से नाता जोड़ा

कानपुर। भीतरगांव के बीटेक इंजीनियर अभिषेक सचान ने 14 लाख का विदेशी पैकेज ठुकराकर इजरायली तकनीक से गांव में खेती शुरू की। अब वे तीन गुना अधिक फसल उगाकर युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं। आज की युवा पीढ़ी खेती को घाटे का सौदा मानती है। लेकिन भीतरगांव ब्लॉक के पतारी और चतुरीपुर गांव के युवा इंजीनियर इस सोच को बदल रहे हैं। लाखों का सालाना पैकेज और विदेश जाने का ऑफर छोड़ गांव आकर खेती को अपनाया और आधुनिक तकनीक के जरिए इसे सफल व्यवसाय के रूप में बदल दिया। भीतरगांव ब्लॉक के पतारी गांव निवासी अभिषेक सचान 12वीं तक पढ़ाई शहर के स्कूल में और अलीगढ़ से बीटेक करने के बाद निजी संचार विभाग कंपनी में बतौर इंजीनियर के पद पर नौकरी ज्वॉइन की। कंपनी ने सालाना पैकेज 14 लाख रुपये देने के साथ विदेश

भेजने का ऑफर दिया। लेकिन नौकरी छोड़कर गांव में खेतीबाड़ी करना शुरू किया। अभिषेक बताते हैं हैं कि इजरायल देश से बाजरा का बीज मंगाकर बुओई की। इससे सामान्य बाजरा की तुलना में तीन गुना अधिक उपज मिला। भुट्टा चार फीट से भी लंबा निकला। अभिषेक इस बार गेहूं व चना बोआई कर नई तकनीक आजमा अजमा रहे हैं। बताते हैं कि प्रति बीघे मात्र 15 किलो आधुनिक गेहूं बीज का छिड़काव किया है। ड्रिप सिंचाई के बाद पूरा खेत गेहूं के किल्लों से भर गया है। इसके अलावा चने का बीच भी बाहर से मंगवाकर बोआई की है। वहीं, भारत सरकार का उपक्रम से कार्यपालक निदेशक के पद से फरवरी में सेवानिवृत्त हुए पतारा ब्लॉक के ककरहिया निवासी संजीव कुमार यादव भूटान में 1200 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना में मैनेंजिग डायरेक्टर के पद के दौरान ड्रैगन फ्रूट की खेती करने की प्रेरणा मिली। सेवानिवृत्त के बाद इसकी खेती करने का मन बनाया। जुलाई में गांव ककरहिया की जमीन में तीन बीघे ड्रैगन फ्रूट का बाग लगाया। संजीव बताते हैं कि मेरा प्रयास इच्छुक किसानों को मार्गदर्शन से उनकी आमदनी बढ़ाना है। दोनो बेंगलुरु में काम कर रहे थे भीतरगांव ब्लॉक के चतुरीपुर गांव निवासी इंजीनियर दंपति ने वर्ष 2022 में बेंगलुरु में नौकरी छोड़कर अपने पैतृक गांव में रसायन-मुक्त प्राकृतिक खेती अपनाई है। अंकुर सचान सॉफ्टवेयर इंजीनियर व उनकी पत्नी रश्मि सचान मैकेनिकल इंजीनियर हैं। दोनो बेंगलुरु में काम कर रहे थे, कोरोना के दौरान वे अपने पैतृक गांव कानपुर लौट आए और रसायन मुक्त खेती करना शुरू किया। रश्मि बताती है कि सह-फसली विधि से एक साथ कई फसलें हल्दी, अमरूद, पपीता, सब्जियां पालक, मेथी, टमाटर, बैंगन उगा लेते हैं।

मऊ में पांच साल बाद शुरू हुई सांसद खेल प्रतियोगिता

मऊ। मऊ में पांच साल बाद सांसद खेल प्रतियोगिता शुरू हुई। इस दौरान पोस्टर से नाम गायब करने का आरोप लगाते हुए घोसी सांसद ने एक्स पर पोस्ट लिखा है। मऊ में पांच साल बाद मंगलवार को तीन दिवसीय सांसद खेल प्रतियोगिता विवादों के साथ शुरू हुई। प्रतियोगिता के पोस्टर में घोसी सांसद राजीव राय का नाम ही गायब था। उधर इसको लेकर सपा सांसद ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कड़ी आपत्ती करते हुए प्रदेश सरकार को घेरा और लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अहंकार और ओछी राजनीति का यह नमूना है। सांसद खेल स्पर्धा में विपक्ष के सांसद को नहीं बुलाना। आप लोगों के घटिया सोच और गिरते हुए राजनैतिक संस्कार का उदाहरण है। जो अहंकारी सत्ता में बैठ कर जनता के ऐतिहासिक आशीर्वाद से जीते सांसद का अपमान करना चाहती है, दरअसल वो घोसी के मालिकों का अपमान है। 27 में जनता अपने अपमान का बदला जरूर लेगी। उधर, सोशल मीडिया पर सांसद के पोस्ट करते ही इस प्रकरण को लेकर अलग- अलग प्रतिक्रियाएं आनी लगी हैं। इस संबंध में जिला खेल अधिकारी डीपी सिंह से बात करने पर उन्होंने कहा कि शासन स्तर से ही समापन सत्र में मुख्य अतिथि के पद पर राज्यसभा के सांसद दर्शना सिंह को नामित किया गया है। ऐसे में एक सांसद के रहते हुए दूसरे सांसद को कैसे बुलाया जा सकता है। वहीं सांसद खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ करने वाले मुख्य अतिथि सीडीओ प्रशांत नागर ने कहा कि सांसद खेल प्रतियोगिता के लिए सांसद को नामित शासन स्तर से किया गया है। पांच साल से नहीं हुई थी सांसद खेल प्रतियोगिता वर्ष 2019 से बसपा

सासंद अतुल राय का कार्यकाल 2024 तक रहा। इनके प्रतिनिधि गोपाल राय ने बताया कि उनके सासंद के कार्यकाल में एक बार भी सासंद खेल प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया गया।

संक्षिप्त खबरें

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन से काफी कुछ सीखने को मिलेगा

गोरखपुर, : पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के तत्त्वावधान में 73वीं अखिल भारतीय रेलवे (पुरुष) कबड्डी चैम्पियनशिप-2025-26 का आयोजन सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम, गोरखपुर में 24 से 28 दिसम्बर,2025 तक किया जायेगा, जिसका शुभारम्भ अध्यक्ष, पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण श्री अभय कुमार गुप्ता 24 दिसम्बर, 2025 को अपराह्न 03.00 बजे करेंगे। इस चैम्पियनशिप-2025 में मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे सहित क्षेत्रीय रेलों एवं उत्पादन इकाइयों की कुल 17 टीमें भाग ले रही है। इस चैम्पियनशिप में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, उत्तर रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, रेलवे बोर्ड, दक्षिण पूर्व रेलवे, पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, रेल व्हील फैक्ट्री, रेलवे सुरक्षा बल, पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स, उत्तर मध्य रेलवे तथा मेजबान पूर्वोत्तर के लगभग 350 खिलाड़ी, कोच, टेक्निकल एवं ऑफिशियल स्टॉफ भाग ले रहें हैं। इस प्रतिस्पर्धा में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी एवं राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक कबड्डी खिलाड़ी इन टीमों का प्रतिनिधित्व करेंगे।73वीं अखिल भारतीय रेलवे (पुरूष) कबड्डी चैम्पियनशिप-2025 के आयोजन से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कबड्डी प्रेमियों को उत्कृष्ट कबड्डी प्रतिस्पर्धा देखने का अवसर मिलेगा तथा यहाँ के उदीयमान खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन से काफी कुछ सीखने को मिलेगा।

विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री ए. के. सक्सेना ने उपस्थित सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया

गोरखपुर,: एन.ई. रेलवे हायर सेकेण्डरी स्कूल एवं एन.ई. रेलवे गर्ल्स इंटर कालेज गोरखपुर में वार्षिक खेलकूद समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में, एन. ई. रेलवे हायर सेकेण्ड्री स्कूल, गोरखपुर में तीन दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता-2025 का शुभारम्भ 23 दिसम्बर, 2025 को मुख्य अतिथि अध्यक्ष रेलवे भर्ती सेल एवं कार्यकारी अधिकारी, एन.ई.रेलवे हायर सेकेण्डरी स्कूल/गोरखपुर श्री राजेश कुमार गुप्ता ने किया। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं के लिए 100 मीटर रेस प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि श्री गुप्ता ने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का परिचय देते हुए छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित किया तथा सदैव खेल भावना से खेलने हेतु प्रेरित किया। प्रधानाचार्य डॉ. बीर. जी. श्रीवास्तव ने धन्यबाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर सीनियर सेकेण्डरी स्कूल के प्रधानाचार्य श्री एस.एस. रावत तथा विद्यालय के शिक्षक, अभिभावक तथा छात्र-छात्राएं उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त एन.ई. रेलवे गर्ल्स इंटर कालेज में 95वीं खेलकूद समारोह का शुभारम्भ 23 दिसम्बर, 2025 को पूर्व सचिव प्रमुख मुख्य लेखाधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे श्री वी. के. पाण्डेय ने किया। इस खेल प्रतियोगिता में 100 मीटर फरार्टा दौड़, रिले दौड़ एवं खो-खो खेल खेले गये। इस अवसर पर श्री पाण्डेय ने कहा कि जो खेलेगा वही खिलेगा। खेल से ही बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। प्रत्येक बच्चों को अपने जीवन में किसी न किसी खेल को प्रमुख हिस्सा बना लेना चाहिए तथा कर्तव्यनिस्ठा से खेलकूद में भाग लेना चाहिए। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री ए. के. सक्सेना ने उपस्थित सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर शिक्षक, अभिभावक तथा छात्राएं उपस्थित थे।

सख्ती के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की बढ़ी रफ्तार 92 भवन हुए पूरे

बस्ती। जिले में प्रस्तावित आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण में बरती जा रही ढिलाई के बाद प्रशासन की सख्ती से गति बढ़ी है। प्रशासन के सख्त तेवर के बाद निर्माण एजेंसी और संबंधित विभागीय अधिकारियों में खलबली है। बताया गया कि शासन स्तर से मिले लक्ष्य में 92 भवन पूर्ण करा लिए गए हैं। साल 2022-23 में मनरेगा कन्वर्जेंस से ग्राम पंचायतों के माध्यम से 27 भवन का निर्माण कराया जाना था, जो पूर्ण बताया जा रहा है। साल 2023-24 में मनरेगा कन्वर्जेंस से 219 आंगनबाड़ी भवन बनाए जाने का लक्ष्य दिया गया है। बताया गया कि अभी तक सिर्फ 92 आंगनबाड़ी भवन के पूर्ण किए जाने की रिपोर्ट दी गई है। यह कार्य ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को मिला है। वहीं, 2024-25 में मनरेगा कन्वर्जेंस से 52 भवनों का निर्माण कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायतों के माध्यम से से कराया जा रहा है। अभी ये भवन पूर्ण नहीं हैं, बताया गया कि सभी निमार्णाधीन हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेश कुमार का कहना है कि जहां खुद के भवन नहीं हैं, वहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन विद्यालय, पंचायत भवन और अन्य शासकीय भवन अथवा किराये पर संचालित किए जाने का प्राविधान है। हालांकि, किराये पर अभी कोई आंगनबाड़ी केंद्र संचालित नहीं हैं। 2655 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित : जिले में वर्तमान में कुल 2655 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिनमें 1848 आंगनबाड़ी केंद्र अभी भी स्कूल और अन्य सामुदायिक भवनों में संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही पंचायत भवन या पब्लिक भवनों में संचालित होते हैं। विभागीय भवनों की संख्या 807 है। नए भवनों के निर्माण से केंद्रों को स्थायी घर मिलेगा।

बोगस फर्म के नाम पर पौने दो लाख शीशी की हुई सप्लाई

बस्ती। कोडीनयुक्त कफ सिरप के धंधे में बस्ती में भी बोगस फर्म के नाम पर सप्लाई का खेल सामने आया है। जिस गणपति फार्मा के नाम पर चार फर्मों ने 1.72 लाख शीशी सिरप की सप्लाई दिखाई थी, एसआईटी की जांच में उस एजेंसी के संचालक पंकज कुमार का नाम-पता सब फर्जी पाया गया है। एजेंसी के पंजीकरण में लगाए गए आधार कार्ड में दिए गए पते पर पंकज कुमार नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला। दिए गए पते पर एजेंसी पहले ही संचालित नहीं मिली थी। अब पंजीकरण और लाइसेंस जारी करने के समय सत्यापन में लापरवाही को लेकर औषधि विभाग के जिम्मेदार भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। कोडीनयुक्त सिरप मामले के तार बनारस, जौनपुर, रांची से लेकर बस्ती तक जुड़े हुए हैं। ईडी और एसआईटी की उच्च स्तरीय जांच की आंच बस्ती तक पहुंच गई है। ईडी के रडार पर कंपनी, सुपरस्टॉकिस्ट, रिटेलर के अलावा औषधि विभाग के जिम्मेदार भी आ गए हैं। पुरानी बस्ती और कोतवाली समेत दो थाना क्षेत्रों में कोडीनयुक्त कफ सिरप की सप्लाई करने वाली छह फर्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। एसपी अभिनंदन ने जांच के लिए एसआईटी गठित की है। दरअसल, नौ दिसंबर को कोडीनयुक्त कफ सिरप की सबसे अधिक 1.72 लाख शीशी खपाने में गणपति फार्मा का नाम आया। औषधि विभाग में गणपति फार्मा के पंजीकरण में संलग्न आधार कार्ड में मालिक के रूप में पंकज कुमार का नाम लिखा है और पता पुरानी बस्ती थानाक्षेत्र के हड़िया चौराहे का दर्ज है।

विजय हजारे ट्रॉफी की बुधवार से होगी शुरूआत रोहित-गिल जैसे स्टार खिलाड़ियों से बढ़ी चमक

बंगलूरू। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे स्टार बल्लेबाज विजय हजारे टूर्नामेंट में खेलते नजर आएंगे। 50 ओवर के प्रारूप में होने वाला यह टूर्नामेंट बुधवार से शुरू हो रहा है। विजय हजारे ट्रॉफी घरेलू वनडे टूर्नामेंट की शुरूआत बुधवार से हो रही है। इस बार इस टूर्नामेंट की चमक बढ़ गई है क्योंकि इसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे भारत के शीर्ष क्रिकेटर उपस्थित होंगे। इन दिग्गज खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने और अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिलेगा। रोहित मुंबई, जबकि कोहली दिल्ली के लिए कुछ मुकाबले खेलेंगे। विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने वाले स्टार खिलाड़ियों की कतार में ऋषभ पंत, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा जैसे नाम भी शामिल हैं, लेकिन कोहली और रोहित जितनी सुर्खियां किसी और को नहीं मिलतीं।

भाजपा चौधरी चरण सिंह के आदर्शों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध

लखनऊ(संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को चौधरी चरण सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने अपना पूरा जीवन गांवों, गरीबों, वंचितों और किसानों के कल्याण तथा समृद्धि के लिए समर्पित कर दिया। योगी किसान दिवस के रूप में मनाई जाने वाली चरण सिंह की जयंती पर किसान नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार किसानों का कल्याण सुनिश्चित करने और भारत रत्न से सम्मानित किसान नेता के आदर्शों को पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। योगी ने सिंह की 123वीं जयंती पर

किसानों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि उनका परिश्रम नमन करने योग्य है। उन्होंने किसान समृद्धि योजना के तहत ट्रैक्टर पाने वाले किसानों के चेहरे की चमक का भी जिक्र किया। आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने विधान भवन प्रांगण स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और ह्यकिसान सम्मान दिवसह्ल पर किसानों को ट्रैक्टर की चाबी दी। साथ ही किसानों, वैज्ञानिकों, एफपीओ आदि को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने चौधरी चरण सिंह सीड पार्क अटारी लखनऊ की प्लॉट आवंटन प्रक्रिया की बटन दबाकर शुरूआत की। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपनी मेहनत से किसानों ने प्रगति की है और 2014 में जब नरेन्द्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली, तब पहली बार किसान भी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बने। उन्होंने कहा, अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना से जोड़ा गया, फिर एक-एक करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से लेकर पीएम किसान सम्मान निधि, एमएसपी की गारंटी हो या बीज से लेकर बाजार तक किसानों की सुविधाओं को बढ़ाया गया। योगी ने सिंह को स्मरण करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के मसीहा, पूर्व प्रधानमंत्री व उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह को ह्यभारत रत्नह्ल देकर किसानों का मान बढ़ाया और लघु व सीमांत किसानों के लिए कृषि ऋण मोचन कार्यक्रम लागू किया। मुख्यमंत्री ने चौधरी चरण सिंह के वक्तव्य का जिक्र किया और कहा, वह हमेशा देश, गांव व किसान के हित में काम करते थे। वह कहते थे कि जब तक किसान गरीब रहेगा, भारत अमीर नहीं हो सकता। ग्रामीण भारत ही असली भारत है। मेरठ के नूरपुर में 1902 में जन्मे दिग्गज जमीनी नेता चरण सिंह ने 28 जुलाई, 1979 से 14 जनवरी, 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इससे पहले वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, धर्मपाल सिंह, डॉ. संजय निषाद, अनिल कुमार, दिनेश सिंह, कपिलदेव अग्रवाल, बलदेव सिंह औलख, गोसेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता समेत भाजपा व रालोद के कई विधायक भी मौजूद रहे।

यूपी विधानसभा सत्र में उठा एसआईआर और बीएलओ की मौतों का मामला

लखनऊ(संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में चुनाव संबंधी कार्यों के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) पर अत्यधिक और असंगत कार्यभार डाले जाने का मामला मंगलवार को विधानसभा में उठाया गया है। कांग्रेस की नेता आराधना मिश्रा ने कहा कि एसआईआर के दौरान मृतक सभी बीएलओ के परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। विधानसभा में कांग्रेस की नेता आराधना मिश्रा ने नियम-56 के अंतर्गत सदन में यह मामला उठाया और एसआईआर पर चर्चा कराने की मांग की। मोना ने कहा कि पर्याप्त संसाधनों के अभाव, अवकाश न मिलने और लगातार फील्ड ड्यूटी के कारण बीएलओ शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यधिक दबाव में काम करने को विवश हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई जिलों मुरादाबाद, बिजनौर, लखनऊ, हाथरस, गोंडा और देवरिया सहित अन्य स्थानों पर ड्यूटी के दौरान या अत्यधिक थकान व तनाव के चलते कर्मचारियों की मौत, हृदयाघात तथा गंभीर शारीरिक क्षति की घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं से संबंधित कर्मचारियों के परिजनों में गहरा आक्रोश है, वहीं आम नागरिकों में भी व्यापक रोष और असंतोष व्याप्त है। सदन में कांग्रेस की नेता मोना ने कहा कि लगातार चुनावी कार्यों का दबाव बीएलओ के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने इस मुद्दे को लोकमहत्व का बताते हुए सदन का तत्काल ध्यान आकृष्ट कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाए, ताकि बीएलओ पर पड़ रहे अत्यधिक कार्यभार को कम करने और उनके स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें। आराधना मिश्रा ने कहा कि चुनाव आयोग और सरकार ने बीएलओ की मौतों का संज्ञान नहीं लिया जो गलत है। काम के दबाव में 10 बीएलओ की मौत हुई है।

अवधी विकास संस्थान द्वारा एक शाम राजू श्रीवास्तव के नाम कार्यक्रम

लखनऊ(संवाददाता)। अवधी भाषा, संस्कृति और लोककलाओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए निरंतर सक्रिय अवधी विकास संस्थान की ओर से विश्वविख्यात हास्य कलाकार, पद्मश्री से सम्मानित एवं उत्तर प्रदेश राज्य फिल्म विकास परिषद के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव की स्मृति में एक भव्य सांस्कृतिक संध्या ह्यएक शाम राजू श्रीवास्तव के नामह्ल का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन उनके जन्मदिन (25 दिसंबर) के अवसर पर शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 को सायं 6रू30 बजे से राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह (भारतखण्डे परिसर), कैसरबाग, लखनऊ में संपन्न होगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अवधी विकास संस्थान के अध्यक्ष एवं आयोजन समिति के प्रमुख विनोद मिश्रा ने लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा, उद्देश्य, अतिथियों की सूची तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजू श्रीवास्तव केवल एक हास्य कलाकार नहीं थे, बल्कि वे जन-जन की आवाज, आम आदमी की पीड़ा और समाज की विसंगतियों को हास्य के माध्यम से मंच पर प्रस्तुत करने वाले एक युगपुरुष थे। उनका जाना भारतीय कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। विनोद मिश्रा ने कहा कि अवधी विकास संस्थान लंबे समय से अवधी भाषा, साहित्य, लोकसंस्कृति और कलाकारों को मंच देने का कार्य कर रहा है। स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव का अवधी भाषा और संस्कृति से गहरा जुड़ाव रहा। वे जहां भी मंच पर जाते थे, अपनी बोली, अपने अंदाज और अपने व्यंग्य से लोगों को हँसाने के साथ-साथ सोचने पर भी मजबूर करते थे। यही कारण है कि उनके सम्मान और स्मृति को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों, साहित्यकारों और सांस्कृतिक कर्मियों को ह्यराजू श्रीवास्तव स्मृति सम्मान 2025ह्ल से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उन व्यक्तित्वों को दिया जाएगा, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है और जो राजू श्रीवास्तव की तरह जनसंवेदनाओं से जुड़े हुए हैं। प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में श्री पवन सिंह, सदस्य विधान परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार, समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉ. हरि ओम (आई.ए.एस.) राज्य मंत्री तथा श्री नटवर गोयल की उपस्थिति रहेगी। इनके अलावा अनेक गणमान्य अतिथि, प्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग, साहित्यकार और कला प्रेमी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। विनोद मिश्रा ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में अवधी और हिंदी लोकसंगीत, गीत-संगीत एवं अन्य प्रस्तुतियां होंगी, जो राजू श्रीवास्तव के व्यक्तित्व और कृतित्व को समर्पित रहेंगी। सांस्कृतिक संध्या में प्रसिद्ध गायक मिथिलेश लखनऊवी एवं डॉ. कुसुम वर्मा अपनी मधुर प्रस्तुतियों से दर्शकों को भावविभोर करेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से न केवल मनोरंजन बल्कि सामाजिक संदेश भी देने का प्रयास किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान विनोद मिश्रा ने कहा कि राजू श्रीवास्तव ने हास्य को केवल हँसी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, भ्रष्टाचार, राजनीतिक विद्रूपताओं और आम आदमी की समस्याओं को अपने व्यंग्य का विषय बनाया। यही वजह है कि वे हर वर्ग में समान रूप से लोकप्रिय रहे। अवधी विकास संस्थान चाहता है कि आने वाली पीढ़ियां उनके विचारों, उनके संघर्ष और उनकी कला से प्रेरणा लें। उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्यक्रम केवल श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन की तरह है, जो लोकभाषाओं और लोककलाओं के संरक्षण का संदेश देता है। अवधी जैसी समृद्ध भाषा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ऐसे आयोजनों की आवश्यकता है। राजू श्रीवास्तव स्वयं लोकभाषाओं के बड़े समर्थक थे और मंच से अक्सर अवधी, भोजपुरी और हिंदी के मिश्रण से अपनी अलग पहचान बनाते थे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संस्थान की संरक्षिका शिवा राजू श्रीवास्तव ने कहा कि राजू श्रीवास्तव का जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका जीवन कलाकारों के लिए प्रेरणास्त्रोत है। उन्होंने अवधी विकास संस्थान के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से कलाकारों को सम्मान और समाज को दिशा मिलती है। प्रेस वार्ता में मौजूद पत्रकारों और मीडिया प्रतिनिधियों से विनोद मिश्रा ने अपील की कि वे इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि समाज के हर वर्ग के लोग इसमें सहभागी बन सकें। उन्होंने कहा कि लखनऊ सांस्कृतिक नगरी है और यहां की जनता कला-संस्कृति को समझती है। ऐसे में यह कार्यक्रम निश्चित रूप से ऐतिहासिक और यादगार बनेगा।

राजधानी में शीतलहर का कहर, नर्सरी व प्री-प्राइमरी स्कूल बंद

लखनऊ(संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन ने 27 दिसंबर तक नर्सरी व प्री-प्राइमरी कक्षाओं को बंद रखने का आदेश जारी किया है। जबकि कक्षा एक से कक्षा आठ तक की कक्षाओं के समय मे परिवर्तन कर दिया है।जिला प्रशासन की तरफ से मौसम विभाग के पूवार्नुमान को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। मंगलवार को जिलाधिकारी लखनऊ विशाख जी ने जनपद के सभी बोर्ड के विद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्री-प्राइमरी और नर्सरी कक्षाओं में 24 दिसंबर से 27 दिसंबर 2025 तक पूर्ण अवकाश रहेगा। वहीं कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यालयों का संचालन समय परिवर्तित किया गया है। इन कक्षाओं की पढ़ाई अब सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही कराई जाएगी। यह व्यवस्था 24 दिसंबर से अगले आदेश तक लागू रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। घने कोहरे और अत्यधिक ठंड के कारण सुबह के समय दृश्यता कम हो रही है, जिससे छात्रों के विद्यालय आने-जाने में परेशानी और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। जिलाधिकारी ने सभी विद्यालय प्रबंधन को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी इस आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

यूपी विधानसभा सत्र, अध्यक्ष सतीश महाना बोले- सदन में आरोप लगाने से पहले सभी सदस्य दें शपथ पत्र

लखनऊ(संवाददाता)। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विपक्ष और सत्तापक्ष के सदस्यों से कहा कि किसी पर आरोप लगाने से पहले उनके समक्ष शपथ पत्र भेजें। समाजवादी पार्टी (सपा) के एक सदस्य ने चीनी मांझे से होने वाले हादसों से संबंधित प्रश्न के लिखित उत्तर से असंतोष जाहिर करते हुए सरकार पर गलत सूचना देने का आरोप लगाया। प्रश्नकाल समाप्त हो जाने की वजह से पूरक प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिलने पर सपा के वरिष्ठ सदस्य रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि सरकार ने उनके प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया है। उनके इस आरोप पर प्रतिरोध करते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सरकार ने सही जवाब दिया है। इस बीच सदन में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि यह परंपरा बन गई है कि जब मंत्रीगण जवाब देते हैं तो सीधा जवाब न देकर पिछली सरकारों पर आरोप लगाते हैं। नियम है कि किसी के ऊपर आरोप लगाने पर सबूत होने चाहिए। यह परिपाटी बंद कराइए, अन्यथा हम लोग उसी समय विरोध करेंगे। पांडेय ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह द्वारा शिक्षा से जुड़े एक प्रश्घ्न पर दिये गये जवाब को लेकर आपत्ति की थी। खन्ना ने कहा कि मंत्री ने किसी दल का नाम नहीं लिया और पिछली सरकारों की बात की है। इस वाद-विवाद के बीच व्यवस्था देते हुए अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा, मैं सभी सदस्यों से कहूंगा, आरोप लगाने से पहले शपथ पत्र मेरे टेबल पर भेज दें। यह सदन के सभी 403 सदस्यों पर लागू होगा। यह प्रश्न पूछने वाले और सरकार के ऊपर भी लागू होगा। कोई भी सदस्य प्रश्न पूछे तो या तो उसे प्रमाणित करेगा, तभी पूछा जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष पांडेय ने इस पर आपत्ति की तो महाना ने कहा कि अब आप पलट गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को तीसरे दिन हाल में दिवंगत पांच पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पूर्व विधायक पूर्णमासी पंकज (भदोही), याद अली (प्रतापगढ़) सैयद अली अशरफी (पीलीभीत), राम सिंह एडवोकेट (मैनपुरी) और लक्ष्मी प्रसाद वर्मा (चित्रकूट) के हाल में निधन होने की जानकारी सदन को दी और उनके जीवन वृत्त पर प्रकाश डाला। महाना ने कहा कि पूर्व सदस्यों के निधन से पूरा सदन शोकाकुल है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वह सदन की ओर से ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति देने की कामना करते हैं। इसके बाद सदन ने दो मिनट का मौन रखा गया। महाना ने कहा कि सभी पूर्व सदस्यों के घर सदन की ओर से दी गई श्रद्धांजलि और शोक संवेदना प्रेषित की जाएगी।

यूपी विधानसभा सत्रः सुरेश खन्ना बोले-सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री को लेकर 7 साल कैद, एक करोड़ रुपये जुमार्ने का प्रावधान

लखनऊ(संवाददाता)। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को संसदीय कार्य व वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री के प्रकाशन को लेकर सख्त कानून की व्यवस्था है और इसमें एक करोड़ रुपये तक के जुमार्ने तथा सात वर्ष कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। खन्ना ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्य डॉक्टर हृदय नारायण सिंह पटेल द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग का प्रश्न उठाए जाने पर सदन को यह जानकारी दी। पटेल ने प्रश्न किया कि क्या प्रदेश में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं अभद्र फोटो, वीडियो अपलोड की रोकथाम की कोई योजना सरकार ने बनाई है और क्या सरकार ऐसे कार्य में लिप्त लोगों को चिह्नित कर दंडात्मक कार्यवाही के लिए कोई नीति बनाएगी? उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए दो मामलों का उदाहरण भी दिया, जिसमें एक ही तरह के मामलों में कार्रवाई में पुलिस ने भेदभाव किया। खन्ना ने मुख्यमंत्री की ओर से जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने इस बात की पूरी व्यवस्था की है कि इस विषय पर जागरूकता कैसे हो और जहां कहीं भी इस प्रकार की शिकायत मिले और शिकायत जिस स्तर की मिले, उस स्तर की कार्रवाई भी हो। मंत्री के बयान पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सरकार से कहा, यह महत्वपूर्ण विषय है, इससे सभी लोग प्रभावित हैं और गलत सूचनाओं का दुष्प्रभाव होता है। उन्होंने कहा कि कोई योजना बनाकर जब तक इस तरह के अपराधियों को सख्त सजा नहीं दी जाएगी, तब तक इसका संदेश नहीं जाएगा। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, समाज में सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करना गलत है लेकिन सरकार ने इसकी रोकथाम की व्यवस्था भी की है। इसमें एक करोड़ रुपये तक के जुमार्ने का भी प्रावधान है। सात साल तक की सजा है। मंत्री ने कहा, जब राष्ट्रीय सुरक्षा की कोई बात आती है तो विशेष सचिव (गृह) को इस बात के लिए अधिकृत किया गया है कि वह इसका संज्ञान लेकर इस संबंध में उचित कार्रवाई करें।

पारिवारिक दलों का गठबंधन है अखिलेश का पीडीएः पंकज चौधरी

लखनऊ(संवाददाता)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनका पीडीए का मंत्र परिवारवाद गठबंधन से ज्यादा कुछ नहीं है। लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को देश की राजनीति का केंद्र बताते हुए कहा कि उनके पास 35 वर्षों का राजनीतिक अनुभव है और वह सभी को साथ लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में कार्यकर्ता सर्वोपरि हैं और आगे भी उनके सम्मान व हितों के लिए निरंतर काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को अटल शताब्दी समारोह मनाया जाएगा। इसी दिन से 31 दिसंबर तक प्रदेश भर में सुशासन दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी विधानसभाओं में अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पंकज चौधरी ने कहा कि 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे, जबकि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी और सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और सभी को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पीडीए का अर्थ श्पारिवारिक दलों का गठबंधन है, जिसका स्वरूप उत्तर प्रदेश के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पहले कल्याण सिंह और वर्तमान में नरेंद्र मोदी को बड़ी जिम्मेदारियां दीं, जो इस बात का प्रमाण है कि पार्टी में कार्यकताओं और नेताओं का सम्मान किया जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा ही ऐसा संगठन है जहां लोकतंत्र पूरी तरह कायम है। आवश्यकता के अनुसार टीम का गठन किया जाता है और पार्टी की जरूरतों के मुताबिक कार्यकताओं को जिम्मेदारियां दी जाती हैं। उन्होंने दोहराया कि भाजपा का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास है और इसी सिद्धांत के तहत काम किया जाता है। पार्टी किसी एक क्षेत्र को मजबूत करने के बजाय पूरे प्रदेश और देश के संतुलित विकास पर ध्यान देती है।

संक्षिप्त खबरें

यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन

लखनऊ(संवाददाता)। उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। यह सत्र 24 दिसंबर तक चलेगा।आज सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। दूसरे दिन की तरह ही आज भी विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। कार्यवाही शुरू होने से पहले यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और शिवपाल सिंह यादव एक ही लिफ्ट से एक साथ जाते हुए नजर आए केशव मौर्य ने वहां मौजूद लोगों से कहा तुम लोग बाहर आओ मुझे शिवपाल जी के साथ जाने दो। आज की कार्यवाही में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। साथ ही जो विधेयक पेश हुए हैं, उन्हें पास किया जाएगा। साथ ही सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया। सरकार की तरफ से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार 24 496.9 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश करती है।

चौधरी चरण सिंह की जयंती पर कोटि कोटि नमन, उनके नाम पर राजनीति हो रही हैः लोकदल

लखनऊ(संवाददाता)। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर लोकदल नेताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर लोकदल नेता सुनील सिंह ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए कहा कि चौधरी साहब किसान, गांव और खेत-खलिहान की आत्मा थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों के हक और सम्मान के लिए समर्पित कर दिया। सुनील सिंह ने कहा कि आज चौधरी चरण सिंह की जयंती पर सरकार बड़े-बड़े आयोजन कर रही है, लेकिन किसानों के नाम पर उनकी विरासत का राजनीतिक और निजी लाभ के लिए उपयोग किया जा रहा है। यदि सरकार वास्तव में चौधरी साहब की विचारधारा पर चल रही होती, तो किसान आज खाद के लिए लाइन में, गन्ना भुगतान के लिए दफ्तरों के चक्कर और फसल के दाम के लिए बाजार में भटकने को मजबूर न होता। सुनील सिंह जी ने किसान सम्मान दिवस पर सरकार के उस बयान- ह्लकिसान ऊर्जा प्रवाहित करता है तो धरती सोना उगलती हैह्व-पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे काव्यात्मक कथन जमीनी सच्चाई नहीं बदलते। धरती तब ही सोना उगलेगी, जब किसान को उसकी फसल का पूरा दाम, समय पर भुगतान और सुरक्षा मिलेगी। जयंती नाम की नहीं, नीति की होनी चाहिए सुनील सिंह ने कहा कि चौधरी चरण सिंह मानते थे कि जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ सकता। आज उनकी जयंती को सरकारी कार्यक्रमों और फोटो सेशन तक सीमित कर दिया गया है, जबकि उनकी सोच के अनुरूप नीतियां लागू नहीं हो रहीं। चुनिंदा किसानों को ट्रैक्टर की चाबी सौंपना सम्मान नहीं, बल्कि दिखावटी राजनीति है। असली सवाल आज भी जस का तस है-सभी फसलों पर कानूनी एमएसपी कब मिलेगी,गन्ना भुगतान समय पर क्यों नहीं हो रहा,खाद-बीज की कालाबाजारी पर रोक क्यों नहीं,आवारा पशुओं से फसल सुरक्षा की स्थायी व्यवस्था क्यों नहीं,चौधरी चरण सिंह की असली नमन तभी होगी, जब किसान को उसकी मेहनत का पूरा मूल्य, सम्मान और सुरक्षा मिलेगी।

शादी करनी है तो मुसलमान बनो कहने वाला केजीएमयू डॉक्टर सस्पेंड

लखनऊ(संवाददाता)। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में महिला डॉक्टर से श्शादी करनी है तो मुसलमान बनो कहने के आरोपी डॉक्टर को मंगलवार को सस्पेंड कर दिया गया। उसके विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई। उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई। सोमवार देर शाम योगी ने लेडी डॉक्टर को फोन किया था। उन्होंने पूरा मामला समझा। पीड़ित डॉक्टर ने सीएम को बताया कि आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक केजीएमयू में गैंग बनाकर धर्मांतरण करा रहा है। इस पर योगी ने कहा निष्पक्ष जांच होगी। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार ने पूरे मामले की केजीएमयू से रिपोर्ट तलब की है। महिला डॉक्टर की सुरक्षा के लिए 24 घंटे सिपाही तैनात कर दिया गया है। जांच के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्कप्लेस एक्ट के तहत गठित विशाखा कमेटी ने केजीएमयू प्रशासन को अपनी रिपोर्ट सौंपी। उसके आधार पर आरोपी डॉक्टर सस्पेंड किया गया। पीड़ित डॉक्टर केजीएमयू से एमडी पैथोलॉजी कर रही है। जबकि आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन सीनियर है। वह केजीएमयू से ही एमडी पैथोलॉजी थर्ड ईयर कर रहा है। रमीजुद्दीन उत्तराखंड जबकि पीड़ित पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। शुरूआती जांच में आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन के खिलाफ सबूत मिलने की बात सामने आई है। 17 दिसंबर को पीड़ित डॉक्टर ने कमरे में दवा की ओवरडोज लेकर आत्महत्या की कोशिश की थी। उन्हें केजीएमयू के आईसीयू एडमिट कराया गया था। पीड़ित के परिवार वाले जब लखनऊ पहुंचे तो 19 दिसंबर को यह पूरा मामला सामने आया था। परिवार का यह भी कहना है कि आरोपी डॉक्टर रमीज ने इसी साल फरवरी में दूसरी हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करवाकर गुपचुप तरीके से शादी कर ली। इधर, सोमवार को पीड़ित लखनऊ में अपने डॉक्टर पिता के साथ महिला आयोग के ऑफिस पहुंचीं। यहां उपाध्यक्ष अपर्णा यादव से मुलाकात की।

चारबाग में आशा वर्कर्स का हंगामा,विधानसभा जाते समय 4 थानों की पुलिस ने घेरकर रोका

लखनऊ(संवाददाता)। राजधानी लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन पर आशा वर्कर्स ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन से सम्बद्ध आल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के बैनर तले प्रदेश भर से आशा वर्कर्स पहुंचीं। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। आशा वर्कर्स का कहना है कि 5 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भीषण ठंड में यूपी के 75 जनपदों से आईं आशा वर्कर्स चारबाग रेलवे स्टेशन पर जुटी। वे स्टेशन से पैदल विधानसभा की ओर कूच करने वाली थीं। इससे पहले ही पुलिस पहुंच गई। 4 थानों की फोर्स ने सभी आशा वर्कर्स को चौतरफा बैरिकेडिंग करके रोक लिया। चारबाग से निकलने के लिए आशा वर्कर से काफी संघर्ष और हंगामा किया, मगर पुलिस ने किसी भी आशा वर्कर को आगे नहीं बढ़ने दिया। इस दौरान आशा वर्कर्स ने नारा लगाया- 2 हजार में दम नहीं, 20 हजार से कम नहीं। फिलहाल सभी आशा वर्कर्स चारबाग रेलवे स्टेशन पर बैठी हैं। लगातार नारेबाजी कर रही हैं। आशा वर्कर्स को 45/46 वे भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुरूप राज्य स्वास्थ्यकर्मी का दर्जा देकर न्यूनतम वेतन, मातृत्व अवकाश, ईएसआई, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और पेंशन गारंटी दी जाए।10 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 50 लाख का जीवन बीमा गारंटी दी जाए। आशा वर्कर्स के काम के घंटे तय किए जाएं। 2017 से अब तक के लम्बित भुगतानों का आकलन कर उसका भुगतान किया जाए। सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए। कानपुर से आईं आशा वर्कर नीतू दीक्षित ने कहा 2006 से सेवा दे रही हूं। इस भीषण ठंड में आना हमारी मजबूरी है। हम लोग पहले से ही सड़कों पर हैं। अब यहां पहुंचकर अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। गुहार लगा रहे हैं। घ्2000 वेतन मिलता है, जिसमें अपने बच्चों का लालन-पालन करना बेहद मुश्किल हो गया है। ना तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं और ना ही बीमार होने पर समय पर इलाज करवा पाते हैं।

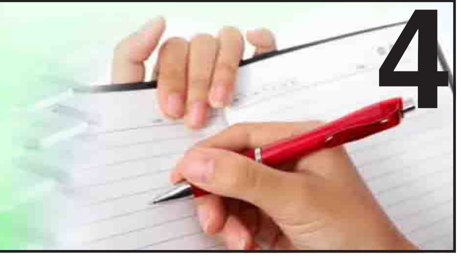

संपादकीय

जानलेवा आबोहवा

देश-दुनिया में दिल्ली में प्रदूषण को लेकर भारी चिंता है, लेकिन यह सिर्फ दिल्ली का ही संकट नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा, उ.प्र. व राजस्थान के कई शहर भी प्रदूषणग्रस्त हैं। इसके अलावा लखनऊ, वाराणसी, जयपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, कानपुर व देश के अन्य शहरों में भी प्रदूषण संकट आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है। हालांकि, इन शहरों में संकट दिल्ली जैसा नहीं है, लेकिन पूरे देश के लिए दीर्घकालीन योजना बनाने की जरूरत तो है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में तीसरे स्थान पर आने वाली दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक का 450 के आसपास बना रहना, निश्चय ही खतरे की घंटी है। दिल्ली सरकार द्वारा उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम-होम, स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई, तोड़फोड़ व निर्माण पर रोक के बावजूद आशातीत परिणाम सामने नहीं आए हैं। इसी बीच, चीन के दूतावास ने दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण में मदद की पेशकश की है। चीनी दूतावास की एक प्रवक्ता ने एक्स पर पोस्ट में स्क्रीनशॉट साझा किया है, जिसमें दिल्ली में एक्यूआई 447 व बीजिंग में 67 दिखाई दे रहा है। निस्संदेह, भारत व चीन दोनों ही तीव्र शहरीकरण की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। लेकिन चीन ने योजनाबद्ध ढंग से उस परिदृश्य को दूर किया है, जिसमें चीन के तमाम शहर सर्दियों में स्मॉग से ढके रहते थे। हालांकि, साम्यवादी चीन व लोकतांत्रिक भारत में नीतियों के क्रियान्वयन में मूलभूत अंतर है। फिर भी चीन की सफलता से सीखा जा सकता है। चीन ने पिछले दो दशकों में आक्रामक ढंग से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाया। वाहन उत्सर्जन पर नियंत्रण किया। लाइसेंस प्लेट लॉटरी व ऑड-ईवन से सड़कों पर वाहनों को कम किया। उसने बड़े मेट्रो-बस नेटवर्क को बढ़ाकर सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाया। करीब तीन हजार के करीब भारी उद्योगों को बीजिंग व आसपास के शहरों से हटाया गया। एक बड़ी स्टील कंपनी को हटाने से घातक कणों में बीस फीसदी की कमी आई। सबसे अधिक जोर कोयले पर आधारित बिजली संयंत्रों व उद्योगों पर रोक लगाने में लगा। इसके अलावा, निर्माण स्थलों पर धूल-रोधी जाली लगाने, पानी के छिड़काव-सफाई, किसानों को पराली भत्ता देने व प्रदूषण के पीक समय में निर्माण पर रोक जैसे कदम उठाए। वहां पौधारोपण को बढ़ावा दिया गया। निस्संदेह, बीजिंग व दिल्ली की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन बीजिंग मॉडल पर विचार होना चाहिए। दरअसल, दिल्ली की भौगोलिक परिस्थिति बीजिंग से भिन्न है, दिल्ली लैंडलॉक्ड क्षेत्र है, आसपास समुद्री इलाका भी नहीं है। लेकिन कोयला आधारित संयंत्रों को बंद करने, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने तथा औद्योगिक संस्थानों को राजधानी की सीमा से बाहर किया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए विशेष बजट की भी व्यवस्था हो। चिंता की बात यह भी है कि दिल्ली की तीन सौ किमी की परिधि में ग्यारह कोयला आधारित पॉवर प्लांट्स हैं, जिन्हें सर्वाधिक प्रदूषण का स्रोत माना जाता है। बहरहाल, दीर्घकालिक नीति बनाने व फैसलों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है।

2026 के लिए क्या कहती हैं भविष्यवाणियां

भविष्यवाणी की गई घटनाओं में दो विश्व युद्ध, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी और अमरीका में 9/11 के आतंकवादी हमले शामिल हैं, ये सभी भविष्यवाणियां 1555 में लिखी गई थीं। उनके लेखों की अस्पष्ट भाषा कई तरह की व्याख्याओं को जन्म देती है और इतिहासकार अक्सर उनकी भविष्यवाणियों की विश्वसनीयता पर बहस करते हैं। 2026 के लिए नोस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियां महत्वपूर्ण वैश्विक अशांति का संकेत देती हैं। पूर्व और पश्चिम के बीच संघर्ष बढ़ेंगे, जिससे एक बड़ा युद्ध हो सकता है, जो लगभग 7 महीने तक चल सकता है। वह स्विट्जरलैंड के टिसिनो क्षेत्र में खून-खराबे की भी चेतावनी देते हैं। कुछ व्याख्याओं का कहना है कि एक शक्तिशाली प्रकाश का आदमी दिखाई देगा, साथ ही और भी जलवायु आपदाएं और तकनीकी बदलाव होंगे। बाबा वेंगा, एक प्रतिष्ठित बल्गारियाई भविष्यवक्ता, ने भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और गंभीर जलवायु परिवर्तन सहित महत्वपूर्ण आपदाओं के बारे में अपनी भविष्यवाणियों के लिए पहचान हासिल की।

कल्याणी शंकर

भविष्यवाणियों में मशहूर फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नोस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियां शामिल हैं, जिनकी भविष्यवाणियों की अलग-अलग तरह से व्याख्या की गई है। भविष्यवाणी की गई घटनाओं में दो विश्व युद्ध, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी और अमरीका में 9/11 के आतंकवादी हमले शामिल हैं, ये सभी भविष्यवाणियां 1555 में लिखी गई थीं। उनके लेखों की अस्पष्ट भाषा कई तरह की व्याख्याओं को जन्म देती है और इतिहासकार अक्सर उनकी भविष्यवाणियों की विश्वसनीयता पर बहस करते हैं। 2026 के लिए नोस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियां महत्वपूर्ण वैश्विक अशांति का संकेत देती हैं। पूर्व और पश्चिम के बीच संघर्ष बढ़ेंगे, जिससे एक बड़ा युद्ध हो सकता है, जो लगभग 7 महीने तक चल सकता है। वह स्विट्जरलैंड के टिसिनो क्षेत्र में खून-खराबे की भी चेतावनी देते हैं। कुछ व्याख्याओं का कहना है कि एक शक्तिशाली प्रकाश का आदमी दिखाई देगा, साथ ही और भी जलवायु आपदाएं और तकनीकी बदलाव होंगे। बाबा वेंगा, एक प्रतिष्ठित बल्गारियाई भविष्यवक्ता, ने भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और गंभीर जलवायु परिवर्तन सहित महत्वपूर्ण आपदाओं के बारे में अपनी भविष्यवाणियों के लिए पहचान हासिल की। ये पर्यावरणीय बदलाव बाढ़, सुनामी और अन्य चरम घटनाओं का कारण बन सकते हैं, जो संभावित रूप से दुनिया भर के क्षेत्रों और सैक्टरों को प्रभावित कर सकते हैं, जिनमें कृषि, बुनियादी ढांचा और आपदा तैयारी शामिल है। हालांकि इन विचारों की वैज्ञानिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है लेकिन उनके संभावित प्रभावों पर विचार करने से हमें भविष्य के जोखिमों को समझने में मदद मिलती है। अगले साल, विभिन्न देशों में 10 चुनाव होने वाले हैं। वे हैं- इथियोपिया, अमरीका, म्यांमार, दक्षिण सूडान, गाम्बिया, सूडान, रूस, जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका और थाईलैंड। दुनिया भर में हर 100 लोगों में से लगभग 7 से 8 लोग इन घटनाओं से प्रभावित हो सकते हैं, जो दिखाता है कि कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं। इन विचारों में एक मजबूत वैज्ञानिक आधार की कमी है। हमें यह सोचने की जरूरत है कि ये अवधारणाएं समाज को कैसे प्रभावित करती हैं।

भारत भी पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। पश्चिम बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तृणमूल कांग्रेस (टी.एम.सी.) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती दे रही है। तमिलनाडु में, अन्नाद्रमुक गठबंधन द्रमुक को सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहा है लेकिन द्रमुक मजबूत और एकजुट बनी हुई है। केरल में, भले ही भाजपा फूट डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन राज्य लैफ्ट डैमोक्रेटिक फ्रंट (एल.डी.एफ.) और यूनाइटेड डैमोक्रेटिक फ्रंट (यू.डी.एफ.) के बीच बंटा हुआ है। असम में, जहां अभी भाजपा सत्ता में है, आने वाले चुनाव में भाजपा और कांग्रेस पार्टी राज्य में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए मुकाबला करेंगी। भले ही वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है, फिर भी इसके मजबूत बने रहने की उम्मीद है, जिससे निवेशकों को भरोसा मिलता है। आघ्टफिशियल इंटैलीजैंस (ए.आई.) में निवेश के कारण विकास दर में सुधार होना चाहिए। अलग-अलग मौद्रिक नीतियों और ज्यादा सार्वजनिक कर्ज पर भी नजर रखनी जरूरी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूस और चीन संसाधनों के लिए मुकाबला कर रहे हैं, जिससे संभावित रूप से संघर्ष हो सकते हैं। यह नोस्ट्राडेमस की राजनीतिक अस्थिरता के बारे में चेतावनियों से मेल खाता है। बुल्गारियाई भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सावधानी बरतने की सलाह दी थी। 2026 तक, विशेषज्ञों को उम्मीद है कि वैश्विक आर्थिक विकास धीमा हो जाएगा। यह मंदी शायद व्यापार तनाव और जनसांख्यिकीय बदलावों, खासकर विकसित देशों में बढ़ती उम्र की आबादी के कारण होगी। अमरीका में 2.2 प्रतिशत की दर से विकास होने का अनुमान है, जो उसकी अर्थव्यवस्था के सामने मौजूदा चुनौतियों को दशार्ता है। गोल्डमैन साक्स रिसर्च का अनुमान है कि 2026 तक, ज्यादातर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में पहले की तुलना में तेजी से विकास होगा। अमरीका के लिए दृष्टिकोण मजबूत है, जो हाल के टैक्स बदलावों, बेहतर वित्तीय स्थितियों और कम टैरिफ के कारण है। भारत में, मुद्रास्फीति 2 प्रतिशत से ऊपर रहने की उम्मीद है, जिससे सामर्थ्य के बारे में महत्वपूण चिंताएं बढ़ रही हैं, खासकर चल रहे व्यापार तनाव और नीतिगत बदलावों के बीच। हालांकि, आटफिशियल इंटैलीजैंस में बढ़े हुए निवेश के साथ-साथ कम टैरिफ से उत्पादकता बढने और महत्वपूर्ण आघ्थक विकास को समर्थन मिलने की उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2026 और उसके बाद के लिए भारत का आर्थिक दृष्टिकोण वैश्विक टैरिफ झटकों और घरेलू नीतियों की प्रभावशीलता से प्रभावित होगा। 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करने के लिए, सरकार को घरेलू विकास को बढ़ावा देने, विदेशी निवेश आकघ्षत करने और वैश्विक बाजारों तक पहुंच का विस्तार करने के बीच संतुलन बनाना होगा। भारतीय आर्थिक दृष्टिकोण वैश्विक टैरिफ झटकों और अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए घरेलू बफर्स और नीतिगत उपायों की क्षमता के बीच तालमेल को दशार्ता रहेगा, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 2026 में, भारत की विदेश नीति पड़ोसी पहले और एक्ट ईस्ट पहलों पर जोर देते हुए मल्टी-अलाइनमैंट रणनीति को लागू करना जारी रखेगी। देश क्वाड (क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग) के जरिए अमरीका और यूरोप, खासकर जर्मनी के साथ रक्षा और आघ्थक सहयोग बढ़ाकर अपनी रणनीतिक सांझेदारी को मजबूत कर रहा है। इसके अलावा, भारत 2026 में अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता का इस्तेमाल ग्लोबल साऊथ के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए करना चाहता है, साथ ही प्रमुख शक्तियों, खासकर अमरीका और चीन के बीच प्रतिद्वंद्विता को भी संबोधित करना चाहता है। यह नीतिगत ढांचा बदलती वैश्विक गतिशीलता के बीच रणनीतिक स्वायत्तता और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने के लिए कनैक्टिविटी, डिजिटल कूटनीति और जलवायु परिवर्तन में पहलों को भी प्राथमिकता देता है।

काम का अधिकार कम न हो, उलटे इसे बढ़ाया जाना चाहिए

इसे मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा-पत्र में भी सम्मिलित किया गया है। श्रम कानून और उचित मजदूरी भी बुनियादी सिद्धांत हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मनरेगा में किए गए बदलावों को समझना जरूरी है। काम के अधिकार के तहत स्थानीय निकायों, विशेषकर पंचायतों, को जिम्मेदारी दी गई थी कि वे स्थानीय स्तर पर चिह्नित परियोजनाओं की सूची से काम उपलब्ध कराएं और उनका क्रियान्वयन करें। मनरेगा ने इसे संस्थागत रूप दिया था। अनेक वर्षों के दौरान डिजिटलीकरण, जीपीएस टैगिंग और मजदूरी के सीधे बैंक खातों में भुगतान से इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत हुई। वहीं राज्यों ने मनरेगा को अन्य बुनियादी ढांचा योजनाओं के साथ जोड़ा, जिससे टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ। लेकिन नई योजना के तहत किए गए बदलाव इस मॉडल से हटने का संकेत देते हैं। चयनित क्षेत्रों और सीमित कार्यों को एक केंद्रीकृत ढांचे में सीमित कर देने से स्थानीय जरूरतों की पहचान कमजोर होगी। खेती के मौसम के दौरान वाले कार्यों को बंद करने से खेत-मजदूर की मोलभाव की क्षमता कमजोर होगी। जबकि पुरानी योजना के तहत मनरेगा ने कृषि मजदूरी को बेहतर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई थी। नई व्यवस्था में चिंता का विषय केवल यही नहीं है कि राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 40ः कर दी गई है- जो पहले सामग्री की लागत का केवल 10ः थी। चिंता का विषय यह भी है कि इससे राज्यों के संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जीएसटी के बाद कर-संग्रह मुख्यतया केंद्र के हाथ में चला गया है ।

डॉ. अरुणा शर्मा

मनरेगा का विचार राइट टु वर्क से प्रेरित था। यूएन ने काम के अधिकार को बुनियादी मानवीय हक माना था। इसे मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा-पत्र में भी सम्मिलित किया गया है। श्रम कानून और उचित मजदूरी भी बुनियादी सिद्धांत हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मनरेगा में किए गए बदलावों को समझना जरूरी है। काम के अधिकार के तहत स्थानीय निकायों, विशेषकर पंचायतों, को जिम्मेदारी दी गई थी कि वे स्थानीय स्तर पर चिह्नित परियोजनाओं की सूची से काम उपलब्ध कराएं और उनका क्रियान्वयन करें। मनरेगा ने इसे संस्थागत रूप दिया था। अनेक वर्षों के दौरान डिजिटलीकरण, जीपीएस टैगिंग और मजदूरी के सीधे बैंक खातों में भुगतान से इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत हुई। वहीं राज्यों ने मनरेगा को अन्य बुनियादी ढांचा योजनाओं के साथ जोड़ा, जिससे टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ। लेकिन नई योजना के तहत किए गए बदलाव इस मॉडल से हटने का संकेत देते हैं। चयनित क्षेत्रों और सीमित कार्यों को एक केंद्रीकृत ढांचे में सीमित कर देने से स्थानीय जरूरतों की पहचान कमजोर होगी। खेती के मौसम के दौरान वाले कार्यों को बंद करने से खेत-मजदूर की मोलभाव की क्षमता कमजोर होगी। जबकि पुरानी योजना के तहत मनरेगा ने कृषि मजदूरी को बेहतर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई थी। नई व्यवस्था में चिंता का विषय केवल यही नहीं है कि राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 40ः कर दी गई है- जो पहले सामग्री की लागत का केवल 10ः थी। चिंता का विषय यह भी है कि इससे राज्यों के संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जीएसटी के बाद कर-संग्रह मुख्यतया केंद्र के हाथ में चला गया है (ईंधन पर वैट और शराब पर उत्पाद शुल्क को छोड़कर)। सीमित संसाधनों वाले राज्य 40ः हिस्सेदारी को वहन करने में असमर्थ रहेंगे, जिसका नतीजा मजदूरी के भुगतान में देरी या काम न मिलने के रूप में सामने आ सकता है। एक और समस्या उस शर्त से जुड़ी है, जिसमें कहा गया है कि काम फंड की उपलब्धता के अनुसार दिया जाएगा। इसका अर्थ है कि काम पर सीमा तय कर दी गई है, जो काम के अधिकार की मूल भावना के विपरीत है। अब काम तभी मिलेगा, जब पैसा होगा। नई व्यवस्था में जिन क्षेत्रों को कार्य के लिए चिह्नित किया गया है, वे भी श्रम की तुलना में अधिक सामग्री-आधारित हैं। उदाहरण के लिए जल परियोजनाओं में अधिकतम खर्च पाइप और टैंक निर्माण पर होता है, यही स्थिति टॉयलेट्स के निर्माण में भी है। इससे श्रम आधारित रोजगार सृजन की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। इसके विपरीत, पहले की व्यवस्था के तहत सड़क निर्माण में मिट्टी के काम, कृषि भूमि में कार्य, कुओं का निर्माण जैसे श्रम-प्रधान कार्य संभव हो पाते थे, जिससे अधिक रोजगार सृजित होते थे। जरूरत इस बात की है कि नई योजना के स्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जाए और कार्यों की उपलब्धता पूरे साल सुनिश्चित की जाए। काम के अधिकार की मूल भावना यह है कि परियोजनाओं की उपलब्ध सूची से, निर्धारित न्यूनतम मजदूरी पर, मांग के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाए और परिसंपत्तियों का निर्माण भी हो। निस्संदेह, इस व्यवस्था में समय-समय पर सुधार की आवश्यकता रही है और आगे भी रहेगी, विशेष रूप से समय पर धन का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए। कार्य क्षेत्रों को सीमित करने की अवधारणा केवल पिछड़े और आदिवासी जिलों तक ही उचित हो सकती है। लेकिन निर्णय लेने का अधिकार विकेंद्रीकृत होना चाहिए। कई बार आपदा की स्थिति में बड़े पैमाने पर काम लेना अनिवार्य हो जाता है- जैसा कि महामारी के दौरान हुआ था। तब प्रवासी मजदूरों के लिए मनरेगा जीवनरेखा साबित हुई थी। मनरेगा पहली ऐसी योजना थी, जिसने मजबूत घरेलू डेटा आधार पर डीबीटी को लागू किया और वित्तीय-समावेश की दिशा में महत्वपूर्ण शुरूआत की। शून्य-बैलेंस खाते खोले गए, जो बाद में बचत खातों में बदले और जमा तथा अन्य बचत लाभों को प्रोत्साहित किया। मनरेगा किसी भी तरह के खाद्यान्न वितरण की तुलना में कहीं अधिक समावेशी योजना साबित हुई थी और मजदूरी के माध्यम से भुगतान ने लाभार्थियों की गरिमा भी बनाए रखी थी। मनरेगा किसी भी तरह के खाद्यान्न वितरण की तुलना में कहीं अधिक समावेशी योजना साबित हुई थी और मजदूरी के माध्यम से भुगतान ने लाभार्थियों की गरिमा भी बनाए रखी थी। इसकी मूल भावना यथावत रहनी चाहिए।

देश में ध्रुवीकरण की कोशिशें तेज

लोकतांत्रिक देश में जनता के विरोध को जान पर खतरे की तरह दिखाना यह बताता है कि प्रधानमंत्री को लोकतंत्र में जनता को मिले अधिकार सुहाते नहीं हैं। खैर, ठंड का मौसम बीतेगा और धुंध खत्म होगी, तब तो नरेन्द्र मोदी को बंगाल में प्रचार के लिए जाना ही होगा, तब अगर विरोध होता है, तो कितनी बार वे लौटेंगे, ये देखना होगा।प.बंगाल में नरेन्द्र मोदी असम गए और वहां उन्होंने इतिहास की गलत बयानी कर पं.नेहरू और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन इस कोशिश में श्री मोदी ने खुद को उपहास का पात्र बना दिया है कि आखिर कब तक वे इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश करेंगे। दरअसल श्री मोदी ने 20 दिसंबर को गुवाहाटी में आरोप लगाया कि शकांग्रेस ने स्वतंत्रता से पहले ही इस जगह की पहचान मिटाने की साजिश रची थी, जब मुस्लिम लीग और ब्रिटिश ताकतें मिलकर भारत को बांटने की जमीन तैयार कर रही थीं, उस समय असम को भी पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना थी। कांग्रेस भी उस साजिश का हिस्सा बनने वाली थी। तब बोरदोलोई जी ने अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े होकर असम की पहचान मिटाने की इस कोशिश का विरोध किया और असम को देश से अलग होने से बचाया।लेकिन हकीकत यह है कि मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए तीन ब्रिटिश कैबिनेट सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था, जिसमें ब्रिटिश भारत के लिए तीन स्तरीय प्रशासनिक संरचना का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें शीर्ष स्तर पर संघीय संघ, निचले स्तर पर अलग-अलग प्रांत और मध्य स्तर पर प्रांतों के समूह थे।

बिहार चुनाव जीतने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प.बंगाल और असम जैसे चुनावी राज्यों में सक्रिय हो गए हैं। बीते दो दिनों में उनकी दो सभाएं प.बंगाल और असम में हुईं। प.बंगाल के नादिया जिले में उनका हेलीकॉप्टर धुंध की वजह से न उतर सका तो उन्होंने कोलकाता से ही वर्चुअली सभा को संबोधित किया, जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल बाहर करने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि नादिया में उनके खिलाफ पोस्टर और बैनर लगे थे, जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या श्री मोदी विरोध का सामना करने से डर गए और इसलिए धुंध को लौटने का कारण बताया जा रहा है। क्योंकि पंजाब चुनाव के वक्त वे किसानों के विरोध की वजह से बीच रास्ते से लौट आए थे और तब उन्होंने कहा था कि अपने मुख्यमंत्री से कहना मैं जिंदा वापस लौट आया। लोकतांत्रिक देश में जनता के विरोध को जान पर खतरे की तरह दिखाना यह बताता है कि प्रधानमंत्री को लोकतंत्र में जनता को मिले अधिकार सुहाते नहीं हैं। खैर, ठंड का मौसम बीतेगा और धुंध खत्म होगी, तब तो नरेन्द्र मोदी को बंगाल में प्रचार के लिए जाना ही होगा, तब अगर विरोध होता है, तो कितनी बार वे लौटेंगे, ये देखना होगा।प.बंगाल में नरेन्द्र मोदी असम गए और वहां उन्होंने इतिहास की गलत बयानी कर पं.नेहरू और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन इस कोशिश में श्री मोदी ने खुद को उपहास का पात्र बना दिया है कि आखिर कब तक वे इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश करेंगे। दरअसल श्री मोदी ने 20 दिसंबर को गुवाहाटी में आरोप लगाया कि शकांग्रेस ने स्वतंत्रता से पहले ही इस जगह की पहचान मिटाने की साजिश रची थी, जब मुस्लिम लीग और ब्रिटिश ताकतें मिलकर भारत को बांटने की जमीन तैयार कर रही थीं, उस समय असम को भी पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना थी। कांग्रेस भी उस साजिश का हिस्सा बनने वाली थी। तब बोरदोलोई जी ने अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े होकर असम की पहचान मिटाने की इस कोशिश का विरोध किया और असम को देश से अलग होने से बचाया।लेकिन हकीकत यह है कि मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए तीन ब्रिटिश कैबिनेट सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था, जिसमें ब्रिटिश भारत के लिए तीन स्तरीय प्रशासनिक संरचना का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें शीर्ष स्तर पर संघीय संघ, निचले स्तर पर अलग-अलग प्रांत और मध्य स्तर पर प्रांतों के समूह थे। उत्तर-पश्चिम भारत, पूर्वी भारत और भारत के शेष मध्य भागों के लिए समूह ए, बी और सी नामक तीन समूहों का प्रस्ताव रखा गया था। समूह ए में हिंदू बहुल प्रांत (जैसे बॉम्बे, मद्रास, यूपी) थे, समूह बी में मुस्लिम बहुल प्रांत (पंजाब, सिंध, उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत) थे और समूह सी में बंगाल और असम, जिसमें बंगाल मुस्लिम बहुल था, जबकि असम हिंदू बहुल। मुस्लिम लीग चाहती थी कि पूरा समूह सी पाकिस्तान का हिस्सा बने। लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। न ही कांग्रेस ये चाहती थी कि असम को बंगाल के साथ मिलाया जाए। 29 दिसंबर 1946 के शहरिजनश अखबार में शगांधीजी की असम को सलाहश शीर्षक से प्रकाशित लेख में इसका स्पष्ट उल्लेख है। नेहरू भी असम को पाकिस्तान या बंगाल के साथ मिलाने के खिलाफ थे। 22 जुलाई 1946 को गोपीनाथ बोरदोलोई को पत्र में नेहरूजी ने लिखा, शसमूह के खिलाफ फैसला करना सही और उचित था।श इसके बाद 23 सितंबर 1946 को लिखा, शकिसी भी हालत में हम असम जैसे प्रांत को उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ करने के लिए मजबूर करने पर सहमत नहीं होंगे।श अप्रैल 1946 में बीबीसी को दिए इंटरव्यू में पं. नेहरू ने कहा, शउत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत में मुस्लिम बहुल होने के बावजूद लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया... असम भी स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के खिलाफ है।श कांग्रेस के जबरदस्त विरोध के बाद अंग्रेजों ने असम को पाकिस्तान में मिलाने की योजना को रद्द कर दिया। कैबिनेट मिशन प्लान को कांग्रेस ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। नेहरू के 10 जुलाई 1946 के प्रेस कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस की स्पष्ट अस्वीकृति और असहमति माना गया। ये सारी बातें सौ साल पुरानी भी नहीं हैं, तब के अखबारों की कतरनों में देखा जा सकता है कि गांधी, नेहरू, कांग्रेस पार्टी और गोपीनाथ बोरदोलोई सबके विचार इस मुद्दे पर एक जैसे थे। लेकिन नरेन्द्र मोदी कह रहे हैं कि बोरदोलोई ने अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े होकर असम बचाया।दरअसल असम में अब भाजपा के खिलाफ एंटीइनकमबेंसी दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस गौरव गोगोई के नेतृत्व में वहां लगातार जमीन पर सक्रिय है।

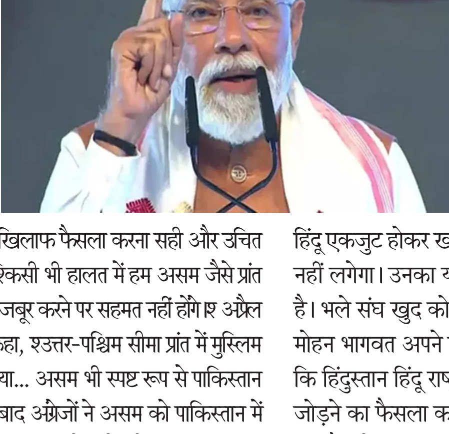

इसलिए भाजपा अब वहां झूठा इतिहास बताकर कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश में है, जिसमें नरेन्द्र मोदी का पहला ही दांव बेकार गया है। असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी भाजपा शुरू से उठाती रही है और हिमंता बिस्वासरमा लगातार सांप्रदायिक विभेद बढ़ाने वाले फैसले ले रहे हैं, इनका लाभ भाजपा को मिलेगा या नहीं देखना होगा।पं.बंगाल में भी नरेन्द्र मोदी यही कोशिश कर रहे हैं। हुमायूं कबीर जैसे नेता बाबरी मस्जिद बनवाने की शुरूआत कर परोक्ष रूप से ध्रुवीकरण में भाजपा की मदद कर रहे हैं। बचा हुआ काम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत पूरा करने की कोशिश में है। श्री भागवत ने रविवार को कोलकाता में कहा कि यदि सभी हिंदू एकजुट होकर खड़े हो जाएं, तो प. बंगाल की स्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उनका यह बयान चुनावी पृष्ठभूमि तैयार करने की तरह देखा जा रहा है। भले संघ खुद को एनजीओ बताए, लेकिन वह खुलकर राजनीति कर रहा है। मोहन भागवत अपने बयान में संविधान की अवहेलना करते भी दिखे, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। अगर संसद कभी संविधान में संशोधन करके वह शब्द जोड़ने का फैसला करती है, तो करें या न करें, ठीक है। हमें उस शब्द की परवाह नहीं है क्योंकि हम हिंदू हैं, और हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है।

दिल्ली हाईकोर्ट सख्त आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनील गावस्कर के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए उनकी अनुमति के बिना नाम, तस्वीर और एआई-डीपफेक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आपत्तिजनक कंटेंट को 72 घंटे में हटाने का आदेश दिया और मामले की अगली सुनवाई 22 मई तय की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर सुनील गावस्कर के व्यक्तित्व अधिकारों (पर्सनैलिटी राइट्स) की अहम रक्षा करते हुए कई वेबसाइटों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को उनकी अनुमति के बिना नाम, तस्वीर या पहचान का व्यावसायिक इस्तेमाल करने से रोक दिया है। कोर्ट ने साथ ही इंटरनेट पर मौजूद आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट को हटाने का भी सख्त आदेश दिया है। अकऔर डीपफेक के दुरुपयोग पर भी रोक जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि सुनील गावस्कर की छवि, आवाज, हाव-भाव या व्यक्तित्व से जुड़े किसी भी तत्व का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (अक) और डीपफेक तकनीक के जरिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी जोनस को क्या है पसंद?

खुद को कहती हैं 'इंडियन प्रिंसेस'

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा हाल ही में कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में नजर आईं। इस शो में प्रियंका ने अपनी बेटी मालती मैरी की पसंद के बारे में बताया। प्रियंका चोपड़ा जोनस भले ही लॉस एंजिल्स में रहती हैं, लेकिन उनका दिल पूरी तरह से भारतीय है। वे अपनी बेटी मालती मैरी जोनस को भारतीय संस्कृति से जोड़े रखने के लिए हर मुमकिन प्रयास करती हैं। हाल ही में 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में आईं प्रियंका ने बताया कि विदेश में रहकर भी वह अपनी बेटी को भारतीय परंपराओं से जोड़े रखती हैं। जब अर्चना पूरन सिंह ने पूछा कि मालती को भारत में होने की क्या कमी महसूस हो सकती

है, तो प्रियंका का जवाब बहुत प्यारा और दिल छूने वाला था। मालती को क्या पसंद है? मालती अक्सर भारत आती-जाती रहती हैं। वह मेरे साथ हैदराबाद, मुंबई, और दिल्ली गई हैं, और यहां तक कि वह अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन भी कर चुकी हैं। प्रियंका ने बताया, 'मैं हमेशा कोशिश करती हूं कि मालती भारतीय संस्कृति और परंपराओं से अच्छे से जुड़ी रहे।' सबसे प्यारी बात जो प्रियंका ने मालती के बारे में बताई, वो यह है कि जब भी मालती घाघरा-चोली पहनती हैं, तो खुद को 'इंडियन प्रिंसेस' कहती हैं। प्रियंका ने बताया, 'मालती को घाघरा, बिंदी और चूड़ियां बहुत पसंद हैं। मैं हमेशा उसके लिए ये चीजें लेकर जाती हूं।' प्रियंका और निक के बारे में प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने दिसंबर 2018 में शादी की थी। शादी के बाद उन्होंने मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन दिया था, जिसमें कई सेलेब्स शामिल हुए। इस जोड़े ने जनवरी 2022 में सरोगेसी से अपनी बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस का स्वागत किया। प्रियंका का वर्कफ्रंट प्रियंका चोपड़ा निर्देशक एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' से भारतीय सिनेमा में वापसी कर रही हैं। यह फिल्म महेश बाबू के साथ है और बहुत बड़ी फिल्म मानी जा रही है। फिल्म की शूटिंग चल रही है। प्रियंका इसमें मंदाकिनी नाम का किरदार निभा रही हैं। कथित तौर पर इस फिल्म में प्रियंका अपने तेलुगु डायलॉग खुद ही डब कर रही हैं।

अमिताभ बच्चन ने देखी धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस, नाती अगस्त्य के डेब्यू पर जाहिर किया प्यार

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन फिल्मों और कलाकारों को लेकर अपनी राय खुलकर रखने के लिए जाने जाते हैं। वह अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स और खासतौर पर अपने ब्लॉग के जरिए सिनेमा से जुड़े अनुभव, विचार और भावनाएं साझा करते रहते हैं। ऐसे में अब हाल ही में अमिताभ ने अपने नाती अगस्त्य नंदा की पहली फिल्म व दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस देखी और इसका रिव्यू किया। अपने ब्लॉग में अमिताभ बच्चन ने लिखा कि इक्कीस उन्हें कई स्तरों पर छू गई। उन्होंने धर्मेंद्र के अभिनय को लेकर भावुक शब्दों में लिखा और कहा कि इतने वर्षों के करियर के बाद भी स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी उतनी ही प्रभावशाली और सशक्त है। बिग बी ने माना कि धर्मेंद्र जैसे कलाकार का सिनेमा में योगदान अमूल्य है और इस फिल्म के जरिए उनका आखिरी अभिनय दर्शकों के दिलों में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। वहीं, अगस्त्य नंदा के डेब्यू को लेकर अमिताभ बच्चन ने गर्व और स्नेह दोनों भावनाएं जाहिर कीं। उन्होंने लिखा कि अगस्त्य का आत्मविश्वास, स्क्रीन प्रेजेंस और काम के प्रति समर्पण उन्हें बेहद प्रभावित कर गया। बिग बी के मुताबिक, अगस्त्य ने अपनी पहली ही फिल्म में मेहनत और ईमानदारी से काम किया है, जो आने वाले समय में उनके करियर के लिए मजबूत नींव साबित हो सकता है।

आगे अमिताभ बच्चन ने फिल्म की टीम, निर्देशन और कहानी कहने के अंदाज की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि इक्कीस एक ऐसी फिल्म है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है और भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ जाती है। बिग बी ने उम्मीद जताई कि यह फिल्म दर्शकों को जरूर पसंद आएगी और खास जगह बनाएगी।

नई फिल्म की तैयारी में जुटे शरद केलकर, जिम से शेयर की फोटो

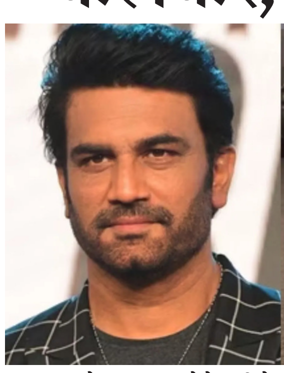

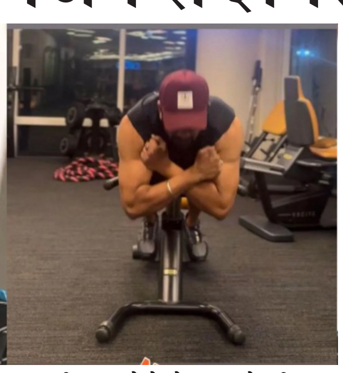

शरद केलकर एक ऐसे अभिनेता हैं जो अपने हर किरदार के लिए पूरी मेहनत और लगन दिखाते हैं। अब उन्होंने अपनी आने वाली, फिलहाल अनटाइटल्ड फिल्म की तैयारी शुरू कर दी है। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने जिम सेशन की एक फोटो शेयर करके दी। इस फोटो के साथ उन्होंने लिखा, और तैयारी शुरू और नीचे लिखा न्यू फिल्म। हालांकि शरद केलकर ने अभी इस फिल्म के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन जिस तरह से वह अपने रोल के लिए मेहनत कर रहे हैं, उससे दर्शकों में काफी उत्सुकता और मउ॰बपजमउमदज है। उनकी तैयारी देखकर साफ है कि वह इस बार कुछ नया और अलग करने वाले हैं, जैसा कि एक मजबूत अभिनेता से उम्मीद की जाती है।

फिलहाल शरद केलकर अपनी आने वाली सीरीज की भी तैयारी कर रहे हैं। इस सीरीज में उनके साथ इमरान हाशमी, अमृता खानविलकर, नंदिश सिंह संधू, अनुराग सिन्हा और जोया अफरोज नजर आएंगे। हाल ही में इस सीरीज का टीजर रिलीज हुआ है, जिसे देखकर दर्शक और ज्यादा उत्साहित हो गए हैं। नीरज पांडे द्वारा बनाई गई यह सीरीज 14 जनवरी 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में सीआईडी के सामने पेश हुई अभिनेत्री लक्ष्मी मांचू, जांच एजेंसियों ने तेज की जांच

हैदराबाद में सीआईडी के ऑफिस के बाहर साउथ अभिनेत्री लक्ष्मी मांचू को स्पॉट किया गया, जहां उन्होंने ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े मामले पर अपना बयान दर्ज करवाया। हैदराबाद में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स के प्रचार से जुड़े मामले में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री लक्ष्मी मांचू मंगलवार को उक्कृकार्यालय पहुंचीं। यह पेशी उन चर्चित चेहरों की बढ़ती सूची का हिस्सा है, जिनसे जांच एजेंसियां अनधिकृत ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स के प्रचार को लेकर पूछताछ कर रही हैं। अभिनेत्री से कई घंटों तक सवाल-जवाब किए गए, जिसके बाद वह उक्कृऑफिस से रवाना हुईं। सीआईडी के कार्यालय पहुंचीं लक्ष्मी मांचू अभिनेत्री लक्ष्मी मांचू को यह समन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जारी किया गया था। जांच एजेंसियों का मानना है कि कुछ ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स को मनोरंजन या चैरिटी से जुड़े अभियानों के रूप में पेश किया गया, ताकि आम लोगों को इनके प्रति आकर्षित किया जा सके। इन प्रचार अभियानों में कई नामचीन हस्तियों की भागीदारी की जांच की जा रही है। सीआईडी और प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि लक्ष्मी मांचू का बयान मामले में पहले से मौजूद डिजिटल सबूतों, बैंक ट्रांजैक्शन्स और अन्य गवाहों के बयानों से मिलान किया जाएगा। जांच एजेंसियां यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि क्या प्रचार के दौरान संबंधित प्लेटफॉर्म्स की वैधता की जांच की गई थी या नहीं, और क्या इसके बदले में किसी तरह का आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ। कई फिल्मी सितारों से हो चुकी है पूछताछ बताया जा रहा है कि यह जांच सिर्फ एक अभिनेत्री तक सीमित नहीं है। बीते कुछ महीनों में कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स और फिल्मी सितारों से भी पूछताछ की जा चुकी है।

धुरंधर में रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना की फैन हुई शिल्पा शेट्टी, डांस स्टेप्स को रिक्रिएट कर बोलीं-ये ट्रेंड करना बनता है

5 दिसंबर को रिलीज हुई आदित्य धर निर्देशित फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है और इसे दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। वहीं बॉलीवुड सेलेब्स से भी इसे लगातार प्यार मिल रहा है। इसमें अब शिल्पा शेट्टी का नाम भी शामिल हो गया है। शिल्पा ने हाल ही में धुरंधर में रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना के डांस स्टेप को रीक्रिएट किया। साथ ही उन्होंने रणवीर सिंह समेत पूरी कास्ट, संगीत और निर्देशक आदित्य धर की जमकर तारीफ की है। शिल्पा शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर अक्षय खन्ना के डांस स्टेप को रीक्रिएट करते हुए एक वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा, ह्लफैन तो मिला नहीं लेकिन मैं फैन बन गई हूं, तो ये ट्रेंड करना बनता था ह्व वीडियो के अंत में शिल्पा मजाक करती हैं कि उनकी टीम पंखा चलाना भूल गई, जिससे उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई। शिल्पा ने अपने पोस्ट में रणवीर सिंह के बारे में कहा, ह्ल/रणवीरसिंह आपका टाइम आ गया३ सहज अभिनय, फिर भी किरदार में एकदम फिट। उन्होंने अक्षय खन्ना की विशेष रूप से प्रशंसा करते हुए लिखा, रुअक्षयखन्ना, ओएमजी ३ ऑरा मैक्स. शिल्पा ने आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त की भी तारीफ करते हुए लिखा, /एक्टरमैडी, आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता था. /रामपाल 72, एक अद्भुत कलाकार. /दत्तसंजय, हमेशा की तरह रॉकस्टार.ह्वशिल्पा ने गौरव गेरा, मानव गोहिल और राकेश बेदी की सराहना करते हुए, कलाकारों की टीम को एकजुट करने के लिए कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा को श्रेय दिया। उन्होंने फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और संगीत की भी तारीफ करते हुए कहा कि यह इस समय उनकी पसंदीदा प्लेलिस्ट है। निर्देशक आदित्य धर की प्रशंसा करते हुए शिल्पा ने कहा, और /आदित्यधर फिल्म्स, आप सचमुच एक दूरदर्शी हैं। आपने लंबे समय में देखी गई सबसे देशभक्तिपूर्ण फिल्मों में से एक बनाई है।धुरंधर की पूरी टीम को सलाम। बता दें, देश में धमाल मचा रही धुरंधर में रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के अलावा संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल अहम भूमिका में नजर आए हैं।

अब बिना इजाजत कोई नहीं कर पाएगा आर माधवन की तस्वीर, नाम और आवाज का इस्तेमाल, दिल्ली एचसी ने लगाई रोक

बॉलीवुड एक्टर आर. माधवन पिछले दिनों अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोर्ट पहुंचे थे। वहीं हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर की याचिका को लेकर एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया है। कोर्ट ने उनके नाम, तस्वीर, आवाज, शक्ल-सूरत और पहचान से जुड़े किसी भी तत्व के व्यावसायिक दुरुपयोग पर सख्त रोक लगा दी है। अदालत ने साफ कहा है कि आर. माधवन की तस्वीर या चेहरे का इस्तेमाल कर किसी भी तरह का कमर्शियल प्रोडक्ट बेचना या प्रमोशन करना गैरकानूनी होगा। इसके अलावा सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद अश्लील, डीपफेक और एआई तकनीक से बनाए गए फर्जी वीडियो, ऑडियो या अन्य कंटेंट को तुरंत हटाने का भी निर्देश दिया गया है। अभिनेता की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट स्वाति सुकुमार ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने आर. माधवन की पहचान का गलत इस्तेमाल करते हुए फर्जी वीडियो, ट्रेलर और आपत्तिजनक सामग्री तैयार की, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। याचिका में यह भी कहा गया कि कोर्ट आने से पहले संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से इस तरह के कंटेंट को हटाने का अनुरोध किया गया था, लेकिन पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन आपत्तिजनक या फर्जी सामग्री हटवाना चाहता है, तो उसे पहले संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म से संपर्क करना चाहिए। इसके बाद भी समस्या बनी रहे तो अदालत का रुख किया जा सकता है। जस्टिस अरोड़ा ने कुछ पक्षकारों के खिलाफ मर्चेंडाइज बिक्री पर रोक लगाई और अश्लीलता से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई के संकेत भी दिए।

पहली बार गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचीं दीप्ति शर्मा

दुबई। भारतीय महिला टीम की ऑलआउंडर दीप्ति शर्मा गेंदबाजी रैंकिंग में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर पहुंच गई हैं। दीप्ति अब टी20 में गेंदबाजों में शीर्ष रैंकिंग की गेंदबाज हैं। भारतीय महिला टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा आईसीसी की जारी नवीनतम टी20 रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई हैं। यह पहली बार है जब दीप्ति गेंदबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची हैं। विशाखापत्तनम में श्रीलंका के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में 28 साल की ऑफ स्पिनर दीप्ति ने 20 रन देकर एक विकेट चटकाया और इस प्रदर्शन की बदौलत ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज एनाबेल सदरलैंड को पछाड़कर शीर्ष पर पहुंच गईं। दीप्ति सदरलैंड से एक रेटिंग अंक आगे दीप्ति ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज से एक रेटिंग अंक आगे 737 अंक के साथ तालिका में शीर्ष पर हैं। तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी पांच स्थान के फायदे से 36वें स्थान पर हैं जबकि स्पिनर श्री चरणी 19 स्थान की लंबी छलांग के साथ 69वें स्थान पर पहुंच गईं। विशाखापत्तनम में 44 गेंद में नाबाद 69 रन बनाकर मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गईं जेमिमा रोड्रिग्स पांच स्थान के फायदे से नौवें स्थान पर हैं।

उस्मान हादी की हत्या से बांग्लादेश में क्यों आया उबाल

ढाका। उस्मान हादी की हत्या के बाद से बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं प्रबल हैं और हिंसा का दौर जारी है। हादी की हत्या का आरोप अवामी लीग के नेता पर लग रहा है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस पूरे मामले में असल में एक बड़ी साजिश हो सकती है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद से वहां भारत विरोधी भावना उफान पर है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी उस्मान हादी को लेकर भारत पर आरोप लगा रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि हादी की हत्या का आरोपी फैसल करीम भी भारत में छिपा हुआ है। हालांकि बांग्लादेश की सरकार ही कह रही है कि फैसल करीम के भारत भागने के कोई सबूत नहीं हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उस्मान हादी की हत्या बांग्लादेश में इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनी हुई है और इससे किसे फायदा है? कट्टरपंथियों की साजिश की आशंका बांग्लादेश की भू-राजनीति के जानकार और इस वक्त पेरिस में रह रहे नाहिद हेलाल ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में दावा किया है कि उस्मान हादी की हत्या से शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग या खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी को नहीं बल्कि जमात ए इस्लामी और बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात को फायदा हो सकता है। नाहिद ने लिखा, 'उस्मान हादी की हत्या के बाद से जो हो रहा है, यही जमात ए इस्लामी के नेता और कट्टरपंथी वर्ग चाहता था। इससे कट्टरपंथियों को अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने, मीडिया संस्थानों को डराने और अवामी लीग के कार्यकताओं की हत्या और सबसे अहम बात चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने का मौका मिल गया है।' बीएनपी की पूर्व सांसद निलोफर चौधरी मोनी ने एक बांग्लादेशी न्यूज चैनल पर पैनल चर्चा के दौरान भी दावा किया कि उस्मान हादी की हत्या से जमात ए इस्लामी को फायदा होगा। उन्होंने कहा, 'उस्मान हादी की हत्या के आरोपी फैसल करीम की दो बार जमानत सुप्रीम कोर्ट के वकील और जमात ए इस्लामी के नेता शिशिर मनीर ने कराई थी। दूसरी बार जमानत तो उस्मान हादी की हत्या से कुछ महीने पहले ही कराई गई थी।' विशेषज्ञों का कहना है कि बांग्लादेश में अस्थिरता, सांप्रदायिक तनाव, अराजकता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गड़बड़ी से सबसे ज्यादा फायदा कट्टरपंथियों को होगा। ऐसे में आशंका है कि उस्मान हादी की हत्या के पीछे कट्टरपंथी हो सकते हैं, जो हादी की हत्या का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। जमात ए इस्लामी को चुनाव में मिल सकता है फायदा उस्मान हादी की हत्या का राजनीतिक कोण एक ये भी है कि उस्मान हादी भारत विरोधी बयानबाजी के चलते कट्टरपंथियों के बीच चर्चित था। साथ ही वह ढाका-8 सीट से आगामी चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ने वाला था। ढाका-8 बांग्लादेश की अहम संसदीय सीट मानी जाती है, जिसके क्षेत्र में ही ढाका यूनिवर्सिटी और संसद भवन आते हैं। यहां से बीएनपी नेता मिर्जा अब्बास और जमात ए इस्लामी की पार्टी छात्र शिबिर के नेता मोहम्मद अबु सादिक भी उम्मीदवार हैं। मिर्जा अब्बास एक बड़ा नाम है और जीत के दावेदार हैं। अब उस्मान हादी की हत्या के बाद जिस तरह से माहौल बना है, उससे जमात के नेता मोहम्मद अबु सादिक को फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश की हिंसा पर जताई चिंता संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बांग्लादेश में हिंसा पर चिंता जताई है, जिसमें देश में एक हिंदू व्यक्ति की लिंचिंग की बर्बर घटना भी शामिल है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने सोमवार को डेली प्रेस ब्रीफिंग में कहा, 'हां, हम बांग्लादेश में हुई हिंसा को लेकर बहुत चिंतित हैं।' दुजारिक ने कहा, 'चाहे वह बांग्लादेश हो या कोई और देश, जो लोग 'बहुसंख्यक' नहीं हैं, उन्हें सुरक्षित महसूस करने की जरूरत है, और सभी बांग्लादेशियों को सुरक्षित महसूस करने की जरूरत है। और हमें विश्वास है कि सरकार हर एक बांग्लादेशी को सुरक्षित रखने के लिए वह सब कुछ करेगी जो वह कर सकती है।' बीते दिनों बांग्लादेश के मयमनसिंह के भालुका इलाके में 25 साल के गारमेंट फैक्ट्री कर्मचारी दीपू चंद्र दास को भीड़ ने कथित ईशनिंदा के आरोप में पीट-पीटकर मार डाला और उसके शव को आग लगा दी। दास की लिंचिंग के सिलसिले में रविवार को दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया। द डेली स्टार अखबार ने पुलिस और रैपिड एक्शन बटालियन (फ्अइ) सूत्रों के हवाले से बताया कि इन नई गिरफ्तारियों के साथ, इस मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

पाकिस्तान में सुरक्षाबलों को फिर बनाया निशाना

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में टीटीपी के हमले लगातार जारी हैं। ताजा हमले में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक पुलिस के वाहन पर हमला कर पांच पुलिसकर्मियों की जान ले ली। हमले के बाद इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश की जा रही है। पाकिस्तान में एक बार आतंकियों ने घात लगाकर सुरक्षाबलों पर हमला किया। इस हमले में पांच पुलिसकर्मी मारे गए हैं। घटना पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा राज्य की है, जहां मंगलवार को अज्ञात हमलावरों ने एक पुलिस की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें वैन सवार पांच पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। रूटीन पेट्रोलिंग पर थे पुलिसकर्मी स्थानीय पुलिस ने बताया कि हमला खैबर पख्तूनख्वा जिले के करक जिले में हुई, जहां पुलिसकर्मी रुटीन पेट्रोलिंग पर थे। इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने पुलिस के वाहन पर हमला कर दिया, जिसमें पांच पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। हमले के बाद पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही हमलावरों की तलाश के लिए भी अभियान शुरू कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने घटना की निंदा की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। सोहेल अफरीदी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बरकरार रखना उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे कायराना हमले सुरक्षाबलों और सरकार के संकल्प को कमजोर नहीं कर सकते। पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि उनके सुरक्षाबलों पर हमले कट्टरपंथी संगठन टीटीपी द्वारा किए जा रहे हैं। खासकर अफगानिस्तान से लगती सीमा पर टीटीपी के हमले लगातार हो रहे हैं।

विदेश मंत्री जयशंकर ने की ढट अमरसूर्या से मुलाकात

कोलंबो। चक्रवात दित्वाह के बाद भारत ने श्रीलंका को 450 मिलियन डॉलर के पुनर्निर्माण पैकेज का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पीएम अमरसूर्या से मुलाकात भी की। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या से मुलाकात कर चक्रवात दित्वाह से हुए नुकसान के बाद देश के पुनर्निर्माण में भारत की पूर्ण प्रतिबद्धता का भरोसा दिलाया। जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में दो दिवसीय दौरे पर श्रीलंका पहुंचे हैं। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच गहरे ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध हैं और आपदा की इस घड़ी में भारत, श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा दिया गया पुनर्निर्माण पैकेज दोनों देशों के आपसी विश्वास और मित्रता का प्रतीक है। इस दौरान जयशंकर ने श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेराथ और राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके की मौजूदगी में उत्तरी प्रांत के किलिनोच्ची जिले में 120 फीट लंबा ड्यूल कैरिजवे बेली ब्रिज का उद्घाटन भी किया। यह क्षेत्र चक्रवात दित्वाह से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में शामिल है। 110 टन वजनी यह पुल भारत से हवाई मार्ग से लाया गया और ऑपरेशन सागर बंधु के तहत स्थापित किया गया। इससे पहले जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से संवेदना और एकजुटता का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि भारत श्रीलंका को 450 मिलियन डॉलर का पुनर्निर्माण पैकेज प्रदान करेगा, जिसमें सड़क, रेल और पुलों की मरम्मत, क्षतिग्रस्त घरों का पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य व शिक्षा क्षेत्र को सहायता, कृषि क्षेत्र में समर्थन और आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करना शामिल है। जयशंकर ने कहा कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन महासागर के तहत श्रीलंका को हरसंभव सहायता दी जाती रहेगी। श्रीलंका में भारत ने बनवाया 120 फीट लंबा बेली ब्रिज भारत ने श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के किलिनोच्ची जिले में 120 फीट लंबा ड्यूल कैरिजवे बेली ब्रिज स्थापित किया है। इस पुल का उद्घाटन विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके और विदेश मंत्री विजिता हेराथ के साथ किया। यह इलाका हाल ही में आए चक्रवात ह्यदित्वाहह्व से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। जयशंकर ने बताया कि 110 टन वजनी इस बेली ब्रिज को भारत से हवाई मार्ग के जरिए लाया गया और ऑपरेशन सागर बंधु के तहत स्थापित किया गया।

हत्यारे साजिद के पास थे छह राइफलों के लाइसेंस

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया में बीते दिनों बॉन्डी बीच पर हुई गोलीबारी के बाद बंदूक लाइसेंस के नियम कड़े करने की तैयारी हो रही है। आरोपी नवीद पर कट्टरपंथियों से संबंध रखने का जांच एजेंसियों को शक था, इसके बावजूद नवीद के पिता को बंदूकों को छह लाइसेंस देने पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी बीच पर हुई गोलीबारी के आरोपी साजिद अकरम को बंदूक का लाइसेंस लेने के लिए कई वर्षों का इंतजार करना पड़ा था। पहले दावा किया जा रहा था कि साजिद अकरम और उसके बेटे नवीद अकरम पर सुरक्षा एजेंसियों को शक था, इसके चलते बंदूक का लाइसेंस मिलने में देरी हुई। हालांकि अब न्यू साउथ वेल्स के प्रधानमंत्री क्रिस मिन्स ने साफ किया है कि शक के चलते नहीं बल्कि प्रशासनिक गड़बड़ी के चलते साजिद अकरम को लाइसेंस मिलने में देरी हुई थी। साजिद को कई साल बाद मिला बंदूक का लाइसेंस साजिद अकरम को पुलिस ने बॉन्डी बीच की घटना के समय ही ढेर कर दिया था, जबकि उसका 24 साल का बेटा नवीद अकरम घायल है। दोनों ने 14 दिसंबर को बॉन्डी बीच पर हनुक्का पर्व मना रहे यहूदियों पर गोलीबारी की थी, जिसमें 16 लोग मारे गए थे। यह ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की सबसे खूनी घटनाओं में से एक है। जांच में पता चला है कि साजिद अकरम के पास छह राइफलों और एक शॉटगन का लाइसेंस था। साजिद ने साल 2000 में बंदूक लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। आमतौर पर इसमें छह से 8 हफ्तों का समय लगता है, लेकिन साजिद को तीन साल पहले ही लाइसेंस मिला था। दरअसल नवीद अकरम के कट्टरपंथियों से संबंधों की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा साल 2019 में जांच की गई थी। इसके बावजूद नवीद के पिता साजिद को बंदूक का लाइसेंस देने पर सवाल उठ रहे हैं। जब इसे लेकर क्रिस मिन्स से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में ऐसा न हो। बंदूक के लाइसेंस देने के नियम सख्त करने की तैयारी बॉन्डी बीच की घटना के बाद ऑस्ट्रेलिया में बंदूक के लाइसेंस देने के नियम कड़े करने की तैयारी है। न्यू साउथ वेल्स की संसद में जल्द ही इस संबंध में कानून पारित हो सकता है। जांच में पता चला है कि आरोपियों ने स्ट्रेट पुल मैकेनिज्म वाली बंदूकों का इस्तेमाल किया, जिससे वे तेजी से फायरिंग कर सके। नए कानून के तहत साजिद जैसे लोगों को स्ट्रेट पुल मैकेनिज्म वाली बंदूकों का लाइसेंस नहीं मिल सकेगा। नए नियमों के तहत सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को ही बंदूक का लाइसेंस मिलेगा और साजिद अकरम जैसे लोग बंदूक नहीं ले सकेंगे। बता दें कि साजिद के पास ऑस्ट्रेलिया में रहने का परमानेंट रेजीडेंट वीजा था। साथ ही संदिग्ध लोगों और जिन पर जांच एजेंसियों को शक है, उन्हें भी बंदूक का लाइसेंस नहीं मिल सकेगा। ऑस्ट्रेलिया में अभी कोई व्यक्ति कितने भी लाइसेंस ले सकता है। एक व्यक्ति के नाम पर तो 298 बंदूके पंजीकृत हैं। अब नए कानून के तहत कोई व्यक्ति अधिकतम चार बंदूकों का ही लाइसेंस ले सकेगा। हालांकि निशानेबाजों और किसानों को अधिकतम 10 बंदूकों का लाइसेंस मिल सकेगा।

कोलकाता से दिल्ली तक प्रदर्शन, ढाका में भारतीय उच्चायुक्त तलब

ढाका। भारत में बांग्लादेशी [illegible] किया है। इस दौरान ढाका ने भारत से अपने राजनयिकों और मिशनों की सुरक्षा मजबूत करने का अनुरोध किया है। भारत में बांग्लादेशी दूतावासों की सुरक्षा को लेकर चिंताओं के बीच, बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को मंगलवार को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय में तलब किया गया। राजनयिक सूत्रों ने इस मामले की पुष्टि की। सूत्रों के अनुसार, नई दिल्ली और कोलकाता सहित भारत के कई हिस्सों में स्थित बांग्लादेशी मिशनों के आसपास उभरती सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर वर्मा को बुलाया गया था। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को बांग्लादेश के विदेश सचिव असद आलम सियाम ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को विदेश मंत्रालय बुलाया। यह बैठक भारत के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर नई दिल्ली और कोलकाता में स्थित बांग्लादेशी मिशनों की सुरक्षा को लेकर बुलाई गई थी। इस दौरान बांग्लादेश सरकार ने भारत से अपने मिशनों और राजनयिकों की सुरक्षा मजबूत करने का अनुरोध किया है। दस दिन में दूसरी बार किया तलब पिछले 10 दिनों में यह दूसरी बार है जब प्रणय वर्मा को तलब किया गया है। इससे पहले 14 दिसंबर को उन्हें 'इंकलाब मंच' के संयोजक शरीफ उस्मान हादी पर हमला करने वाले आरोपियों को पकड़ने में सहयोग के लिए बुलाया गया था। गौरतलब है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कार्यकाल में भारतीय राजदूत को अब तक छह बार तलब किया जा चुका है। अत्याचार के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन वहीं दूसरी ओर कोलकाता में बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के विरोध में सैकड़ों लोगों ने मार्च निकाला। कोलकाता में 'बोंगियो हिंदू जागरण' के बैनर तले सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने 'हिंदू हुंकार पदयात्रा' निकाली। भगवा झंडे लिए प्रदर्शनकारी सियालदह से बांग्लादेश उप उच्चायोग की ओर बढ़ रहे थे, जिन्हें बेकबागान इलाके में भारी पुलिस बल ने रोक दिया। पुलिस ने किया लाठीचार्ज जब प्रदर्शनकारियों ने उप उच्चायोग के करीब जाने के लिए पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की, तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदर्शनकारी बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और हाल ही में हुई एक हिंदू युवक की लिंचिंग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। क्या है प्रदर्शन की मुख्य वजह? प्रदर्शनकारियों का मुख्य आक्रोश 18 दिसंबर को बांग्लादेश के मैमनसिंह में हुई दीपू चंद्र दास (25) की नृशंस हत्या को लेकर था। मामले में गारमेंट फैक्ट्री वर्कर दीपू पर ईशनिंदा का आरोप लगाकर भीड़ ने उसे पीटा, पेड़ से लटकाया और बाद में उसके शव को ढाका-मैमनसिंह हाईवे के पास आग के हवाले कर दिया।

एक मंच पर साइप्रस-ग्रीस-इस्राइल अशांत पश्चिम एशिया में सहयोग और सुरक्षा पर मंथन

यरूशलम। यरुशलम शिखर सम्मेलन में साइप्रस, ग्रीस और इस्राइल ने बढ़ती क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच एकजुट होकर सुरक्षा, ऊर्जा और कनेक्टिविटी में सहयोग मजबूत करने का संकल्प लिया। नेताओं ने ग्रेट सी इंटरकनेक्टर को क्टएउ से जोड़ने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे अब तक की सबसे अहम बैठक बताया और कहा कि आतंकवाद व आक्रामकता के दौर में सहयोग अनिवार्य है। पश्चिम एशिया और पूर्वी भूमध्यसागर में बढ़ती अस्थिरता के बीच साइप्रस, ग्रीस और इस्राइल ने यरुशलम शिखर सम्मेलन में एकजुटता दिखाई। तीनों देशों ने सुरक्षा, ऊर्जा और कनेक्टिविटी में सहयोग गहरा करने और क्षेत्रीय शांति व समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। तीनों देशों के नेताओं ने साफ किया कि क्षेत्र में बढ़ती भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद वे आपसी सहयोग को न सिर्फ जारी रखेंगे, बल्कि और मजबूत भी करेंगे। इस दौरान तीनों देशों के तीनों नेताओं ने ग्रेट सी इंटरकनेक्टर (जीएसआई) परियोजना को आगे बढ़ाने और इसे इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (क्टएउ) से जोड़ने पर भी सहमति जताई। इससे क्षेत्र में ऊर्जा और व्यापारिक संपर्क और मजबूत होने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन को लेकर क्या बोले नेतन्याहू? शिखर सम्मेलन को लेकर संयुक्त प्रेस वार्ता में इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह तीनों देशों की दसवीं बैठक थी, लेकिन उनके लिए यह अब तक की सबसे अहम बैठक है। उन्होंने कहा कि पिछली मुलाकात 7 अक्टूबर की घटना से कुछ समय पहले हुई थी, जिसने यह याद दिलाया कि इस क्षेत्र में स्थिरता हमेशा बनी रहे, यह जरूरी नहीं है। नेतन्याहू ने कहा कि पश्चिम एशिया और पूर्वी भूमध्यसागर आज आक्रामकता, आतंकवाद और अस्थिरता की परीक्षा से गुजर रहे हैं। ऐसे समय में ताकत, स्पष्ट सोच और सहयोग कोई विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत है। तीनों देशों के सहयोग से खुलेंगे नए अवसर इस दौरान नेतन्याहू ने इस बात पर भी जोर दिया कि तीनों देशों का सहयोग न केवल सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि समृद्धि के नए अवसर भी पैदा करता है। ऊर्जा, तकनीक, कनेक्टिविटी और सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों में मिलकर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही इतिहास का जिक्र करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि कभी इन तीनों देशों पर साम्राज्यों ने शासन किया था, लेकिन संघर्ष और बलिदान के बाद उन्होंने स्वतंत्रता हासिल की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग पुराने साम्राज्य फिर से खड़े करने का सपना देख रहे हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि यह अब संभव नहीं है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने क्या कहा? वहीं इस शिखर सम्मेलन को लेकर साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडूलिडेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में तीनों देशों ने अपने गठबंधन की रणनीतिक अहमियत को दोबारा पुष्टि की है। यह गठबंधन साझा मूल्यों, आपसी हितों और समान लक्ष्यों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यह सहयोग क्षेत्रीय एकीकरण, स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि की दिशा में काम कर रहा है। गाजा की स्थिति पर भी बोले निकोस क्रिस्टोडूलिडेस निकोस ने गाजा की स्थिति को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि साइप्रस राष्ट्रपति ट्रंप की 20-बिंदुओं वाली योजना और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 के पूर्ण क्रियान्वयन का समर्थन करता है। उन्होंने मानवीय सहायता में साइप्रस की भूमिका पर भी जोर दिया। साथ ही अमालथिया परियोजना के जरिये साइप्रस गाजा तक मानवीय मदद पहुंचाने, सुरक्षा और त्वरित पुनर्बहाली के प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। साथ ही उन्होंने 3+1 प्रारूप (साइप्रस, ग्रीस, इस्राइल और अमेरिका) की अहमियत बताई और कहा कि इससे क्षेत्रीय सहयोग और भी मजबूत होता है तथा स्थिरता और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलता है। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने क्या संदेश दिया? इसके अलावा ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने कहा कि तीनों देश क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कूटनीतिक और स्थिरता लाने वाले प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि भले ही भू-राजनीतिक हालात कठिन हों, लेकिन यह सहयोग समय की कसौटी पर खरा उतरा है। उन्होंने बताया कि यह त्रिपक्षीय सहयोग पूर्वी भूमध्यसागर में शांति, सुरक्षा और स्थिरता में अहम योगदान दे रहा है और भविष्य में एक मजबूत क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे के निर्माण का रास्ता खोलता है।

दक्षिण कोरिया में विद्रोह मामलों के लिए विशेष अदालतों को मंजूरी

सिओल । दक्षिण कोरिया की संसद ने विद्रोह, राजद्रोह और विदेशी षड्यंत्र से जुड़े मामलों के लिए विशेष अदालतें गठित करने का कानून पारित किया। दक्षिण कोरिया की संसद ने विद्रोह, राजद्रोह और विदेशी साजिश से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित करने से संबंधित विधेयक को पारित कर दिया है। यह फैसला उस समय लिया गया है, जब जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ चल रहे विद्रोह मामले की सुनवाई में देरी को लेकर सरकार पर सवाल उठ रहे थे। इस कानून के तहत सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सियोल हाई कोर्ट में ऐसे मामलों के लिए कम से कम दो विशेष पीठों का गठन किया जाएगा। हर पीठ में तीन न्यायाधीश होंगे, जिनका चयन संबंधित अदालत की जज काउंसिल करेगी। सरकार और विपक्ष के बीच टकराव यह विधेयक 175-2 के भारी बहुमत से पारित हुआ, जबकि कई कंजरवेटिव सांसदों ने मतदान का बहिष्कार किया। विपक्षी पीपल पावर पार्टी ने इसे न्यायिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करार दिया और ली जे म्युंग से कानून को वीटो करने की मांग की। पीपीपी नेता जांग डोंग-ह्युक ने संसद में 24 घंटे का फाइलबस्टर भी किया और आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी अदालतों पर दबाव बना रही है। यून सुक योल केस से क्यों जुड़ा है कानून पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल ने दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू कर सत्ता बनाए रखने की कोशिश की थी। हालांकि कुछ ही घंटों में उनका प्रयास विफल हो गया। अप्रैल में उन्हें पद से हटा दिया गया और जुलाई में दोबारा गिरफ्तार किया गया। उन पर विद्रोह, सत्ता पलटने की साजिश और संविधान के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप हैं, जिनमें उम्रकैद या मौत की सजा तक का प्रावधान है।

जापान के पूर्व सम्राट की सेहत में सुधार दिल की हालत स्थिर

जापान के पूर्व सम्राट अकिहितो ने मंगलवार को अपना 92वां जन्मदिन मनाया। इसके साथ ही महल की ओर से जारी आधिकारिक बयान में बताया गया है कि उनकी हृदय स्थिति स्थिर है। जापान के पूर्व सम्राट अकिहितो ने मंगलवार को अपना 92वां जन्मदिन मनाया। वहीं, महल के अधिकारियों ने बताया कि इस साल की शुरूआत में उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी, हालांकि अभी उनकी हृदय स्थिति स्थिर है। शाही परिवार एजेंसी ने एक बयान में कहा कि सम्राट नारुहितो के पिता अकिहितो को मई में हृदय की मांसपेशियों में अपर्याप्त रक्त प्रवाह की समस्या का पता चला था, लेकिन जुलाई में नई दवा शुरू करने के बाद से उनकी स्थिति स्थिर है। परिवार के साथ मनाने वाले है जन्मदिन एजेंसी ने बताया कि उन्हें अभी भी गोबी मछली पर वैज्ञानिक शोध करना पसंद है, यह उनका करियर का वह काम है जिसमें उन्होंने 10 नई प्रजातियों की खोज की थी, और वह सप्ताह में दो बार महल परिसर में स्थित एक जीव विज्ञान प्रयोगशाला का दौरा करते हैं। अकिहितो, जिन्होंने 2019 में अपने पदत्याग के बाद से सम्राट एमेरिटस की उपाधि धारण की है, अपने परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाने और जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची सहित मेहमानों का स्वागत करने वाले थे।

मंत्र भारत : RNI-MPHIN/2023/88414 देवांश प्रिंटिंग प्रेस 12/12 विनय नगर सेक्टर-2 ग्वलियर(म.प्र.) से मुद्रित एंव 433 आनंन नगर डबल रोड बहोड़ा ग्वालियर से प्रकाशित एवं सम्पादित।
E-Mail : mantragwalior@gmail.com | सम्पादक : मनीष शुक्ला, मोबाइल : 7007837917 स्थानीय संपादक- आनंद त्रिवेदी | वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे का क्षेत्र ग्वालियर न्यायालय होगा।